RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

यदि आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो अपने जीने के तरीके को बदलें।

गौर गोपाल दास

वर्ष-08, अंक - 45 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 27 अगस्त 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

हंगामा ज्यादा... बहस कम... क्या यही है माननीयों का काम...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

हाल ही में हुए मानसून सत्र में 12 विधेयक पास हुए जिसमें से 11 विधेयक बिना चर्चा के पास होना तथा पूरे मानसून सत्र में केवल 19 प्रतिशत कार्य होना सदन में माननीयो की कार्यशैली को दर्शाता है। संसद जो कि आम जनता की टैक्स रूपी गाड़ी कमाई से चलती है और माननीय भी इसीलिए चुने जाते हैं कि वे संसद में बैठकर जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा करें। पक्ष जहां अपनी बात रख कर सदस्यों को नए विधेयक पर चर्चा के लिए रखते हैं तथा विपक्ष का यह दायित्व रहता है कि, वे सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों का विश्लेषण कर उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए सार्थक बहस करें। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि, जब भी संसद का सत्र आहुत किया जाता है तब किसी तात्कालिक मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी हो जाती है। और यह तनातनी संसद के कार्यों पर भी प्रभाव डालती है और तत्कालीन मुद्दे की आड़ में जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती है।

संसद का यह मानसून सत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया... जो पिछले 22 वर्षों में सबसे कम कामकाज वाला रहा। यही नहीं सत्र के अंतिम दिन जब लोकसभा में सभी सांसद बैठे तो महज 4 मिनट में वंदे मातरम गायन के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित कर दी गई, वहीं राज्यसभा भी महज 1 घंटे के लिए ही चल पाई। रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 22 साल में किसी भी मानसून सत्र में कार्य की दृष्टि से यह सबसे कम काम रहा लोकसभा में 15 प्रतिशत तो राज्यसभा में 33 प्रतिशत ही कार्य हुआ और अधिकांश बिल बिना बहस के ही पास हो गए। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा 1126 मिनट तो राज्यसभा में 1881 मिनट ही काम हो सका दोनों सदनों का कामकाज 23.18 प्रतिशत ही रहा। संसद का सबसे खराब सत्र 2010 का शीतकालीन सत्र था जब लोकसभा में 5 प्रतिशत तो राज्यसभा में केवल 12 प्रतिशत ही काम हुआ था उस समय 2जी घोटाले को लेकर संसद ठप थी।

यही नहीं 2013 के शीतकालीन सत्र में भी लोकसभा में 8 प्रतिशत तो राज्यसभा में 19 प्रतिशत कामकाज ही हुआ था। संसद के सत्र पर प्रति मिनिट लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इस हिसाब से पूरे सत्र में लगभग 150 करोड रुपए खर्च हुए और कामकाज बहुत कम हुआ। ऐसे में आम जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी ही हुई है आम जनता यह अपेक्षा करती है कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके हक की आवाज संसद में उठाएंगे। लेकिन आम जनता जब अपने माननियो को इस प्रकार हंगामा करते हुए देखते हैं तो यह सोचने पर मजबूर है कि, क्या इसलिए वे अपने माननीय को चुनकर भेजते हैं...?

सदन में सार्थक चर्चा न होना सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है। आज भी देश में अटल जी के कटाक्ष की चर्चा होती है कि, वे अपनी बात कितनी सहज रूप से कह देते थे और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कहावत चरितार्थ करते थे। जब अटल जी विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री को दुर्गा कहकर संबोधित किया था। लेकिन आज का विपक्ष प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच का छोटा... जैसे फरहीन शब्दों का प्रयोग करके न केवल अपनी विश्वनियता बल्कि सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है।

असहमती होना अलग बात है, अटल जी स्वयं कहते थे कि राजनीति में मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि, वो विपक्ष की आवाज को देशद्रोह न समझे बल्कि देश हितेषी भी समझे और विपक्ष की आवाज को उचित महत्व दे।

बहुत हुई महंगाई की मार...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क। मुजम्मिल मंसुरी

2014 के चुनाव में भाजपा ने एक नारा दिया था जो काफी चर्चित हुआ था।, बहुत हुई महंगाई की मार... अबकी बार मोदी सरकार...। वर्तमान परिदृश्य में यही नारा मोदी सरकार की गले की हड्डी बन गया है। सबका साथ और सबका विकास का नारा भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और यह बदलकर सबका साथ... और उद्योगपतियों का विकास... बन कर रहा गया है। पेट्रोल-डीजल के बाद शक्कर और तेल के दामों में बढ़ोतरी से सरकार, आम आदमी के निशाने पर आ गई है। लोग अपनी भड़ास सोशल साइटों पर निकाल रहे हैं।

शक्कर के दामों में अप्रत्याशित तेजी और राखी के त्यौहार को देखते हुए आम आदमी अपना गुस्सा सरकार के प्रति दिखा रहा है। लोगों का कहना है कि, सरकार ने राखी के त्योहार पर आम व्यक्ति के मुंह से मिठास छीन ली है। वहीं पेट्रोल में इथेनाल मिलाने को लेकर भी आम जनता में रोष है। लोगों का कहना है कि, सरकार ने पेट्रोल में इथेनाल तो मिला दिया लेकिन शक्कर के बारे में कुछ नहीं सोचा जिसके बाद शक्कर के दाम अपने उच्चतम स्तर 72 रुपए तक पहुंच गए थे।

सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह वक्तव्य भी खूब वायरल हो रहा है जब शक्कर 20 रुपए किलो तक पहुंच गई थी और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अटल जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार को घेरा था।

भारत कोई धर्मशाला नहीं: अमित शाह

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार का सख्त रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश में रहने का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही है। अन्य विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के लिए वैध माध्यम से सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा।

अमित शाह ने कहा कि देश को कम से कम समय में घुसपैठियों से मुक्त करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों से सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठ देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय स्थिति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

उन्होंने बताया कि, पिछले आठ महीनों में गृह मंत्रालय ने सभी भूमि सीमा वाले राज्यों का दौरा कर सीमा सुरक्षा को लेकर राज्यों के साथ विस्तृत कार्ययोजना साझा की है। प्रत्येक राज्य में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सीमा सुरक्षा और घुसपैठ से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने पर भी जोर दिया गया।

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जो विदेशी नागरिक वैध माध्यम से भारत आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था तथा विकास में योगदान देते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बीपीएससी विवाद के बीच कुत्ता जनता पार्टी का नया ट्रेंड, छात्रों ने लगाए नारे

पटना।

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच चल रहे विवाद ने नया रूप ले लिया है। आयोग के एक अधिकारी की टिप्पणी से नाराज छात्रों ने विरोध जताने के लिए 'कुत्ता जनता पार्टी' नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसका नाम और उससे जुड़े वीडियो सामाजिक माध्यमों पर चर्चा में हैं।

वायरल वीडियो में कुछ छात्र हाथों में बैनर लेकर कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। बैनर पर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने छात्रों की तुलना कुत्तों से की और वे इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे।

मामले की शुरुआत बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की एक टिप्पणी से हुई। पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सवाल पूछा गया था। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है।

सवालों के जवाब में राजेश कुमार सिंह ने एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा था, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इसके बाद उनका यह बयान सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हो गया और छात्रों में नाराजगी बढ़ गई। छात्रों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और विरोध के लिए कुत्ता जनता पार्टी नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

विवाद बढ़ने के बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार और आयोग के अधिकारी पर निशाना साधा। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अधिकारी से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने सरकार से भी मामले में कार्रवाई की मांग की।

विवाद बढ़ने के बाद राजेश कुमार सिंह ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक कहावत का इस्तेमाल किया था और उनकी बात को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है।

हाईकोर्ट में फर्जी वकील बनकर घूम रहे युवक को पकड़ा

जबलपुर। हाईकोर्ट से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक खुद को वकील बताकर न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने और न्यायाधीशों के सामने बहस करने का दिखावा कर रहा था। युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी तैयार किया, जो बाद में सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हो गया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार युवक ने वकील की तरह पोशाक पहनकर बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर न्यायालयीन कार्यवाही में शामिल होने का नाटक किया। वह न्यायाधीश के सामने अंग्रेजी में बहस करता हुआ दिखाई दिया। युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय की ओर से पुलिस को युवक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि युवक ने न्यायालय की कार्यवाही और वकील के रूप में अपनी मौजूदगी को लेकर भ्रामक वीडियो तैयार किया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

प्रेमिका के लिए एमपीएससी का प्रश्नपत्र लीक कराने का आरोप, परीक्षा रद्द

मुंबई। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की औषध निरीक्षक, ग्रुप-बी भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस जांच में पेपर लीक की साजिश का खुलासा होने के बाद आयोग ने 22 मार्च 2026 को आयोजित परीक्षा की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। मामले में डच्ब्ू के तीन कर्मचारियों सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषध निरीक्षक के पदों के लिए 22 मार्च को राज्य के छह संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र अथवा उसके प्रश्न पहुंच गए थे। शिकायतों के आधार पर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जांच शुरू की।

पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका को परीक्षा में सफल कराने के लिए एमपीएससी के कर्मचारियों की मदद से प्रश्नपत्र हासिल किया। जांच में यह भी सामने आया कि प्रश्नपत्र कथित तौर पर उसी महिला अभ्यर्थी तक पहुंचाया गया था। मामले में पेपर उपलब्ध कराने में मदद करने वाले एमपीएससी के तीन कर्मचारी, कथित मुख्य सूत्रधार युवक, एक क्लास संचालक और अभ्यर्थी के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले में पहले पेपर लीक को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आए थे। हालांकि बाद की पुलिस जांच में एक अभ्यर्थी के परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल करने की बात प्रथमदृष्टया सामने आने के बाद आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया। आयोग ने परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।

इस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम 12 जून को घोषित किया गया था। कुल 506 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया था, जिनमें से 488 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इसके बाद 488 अभ्यर्थियों की अस्थायी मेरिट सूची भी जारी की गई थी। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी।

तीन हजार करोड़ के लेन-देन की खबरों से क्षेत्र में कोतूहल का माहौल

यूपी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया

माही की गूंज, झाबुआ/ पेटलावद। राकेश गेहलोत

जिस अंकों की राशि की बात हम कर रहे है वो अधिकाश अखबारों में पढ़ने सुनने मिलती हैं। वो भी सरकार की योजनाओं में खर्च होने वाली राशि की जानकारी में इस प्रकार के आंकड़े पढ़ने सुनने को मिलते है। लेकिन शनिवार को पेटलावद थाना क्षेत्र ग्राम रूपगढ़ पहुंची यूपी की लखनव पुलिस ने जब रूपगढ़ के युवक विनोद राठौर को उठाना उसके बाद तीन हजार करोड़ के फर्जी लेन-देन के बड़े व्यापार की चर्चा ने पूरे क्षेत्र में कोतूहल का माहौल बना दिया।

जितने मुंह उतनी बात ओर उतने ही आंकड़े, लखनव पुलिस ने युवक विनोद राठौर को हिरासत में लेकर पेटलावद न्यायालय में पेश किया जहां से विनोद राठौर को कस्टडी लखनव पुलिस को दी गई ओर वो हिरासत में लिए गए युवक को लेकर लखनव रवाना हो गई। साइबर फॉड से जुड़े एक बड़े और सनसनीखेज मामले में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र से एक व्यक्ति को दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रूपगढ़(पेटलावद) गांव निवासी विनोद गोपाल राठौर के रूप में हुई है। जिसे स्थानीय पेटलावद कोर्ट में पेश करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले जाया गया है।

- आरोपी विनोद राठौर।

यह पूरी कार्रवाई देशभर में फैले कथित फर्जी आईपीओ और शेयर बाजार धोखाधड़ी के एक विशाल सिंडिकेट की जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह पूरा मामला लगभग तीन हजार करोड़ रुपए के भारी-भरकम वित्तीय लेन-देन और साइबर फॉड से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, इस बड़े नेटवर्क का संचालन अनुराग श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा था, जो लोगों को फर्जी आईपीओ, शेयर बाजार और आकर्षक निवेश योजनाओं के नाम पर चूना लगाते थे।

एसटीएफ की जांच में विनोद गोपाल राठौर को पिक्सलर कंपनी का मालिक बताया गया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि, राठौर ने मुख्य आरोपी अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में रहकर इस अवैध नेटवर्क का सहयोग किया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि, राठौर ने वर्ष 2022 में एक गेमिंग कंपनी शुरू करने में मदद की थी, जिस पर संदेह है कि इसका इस्तेमाल साइबर फॉड से हासिल अवैध रकम को छिपाने और उसे अलग-अलग चैनलों के जरिए घुमाने के लिए किया गया था। हालांकि, अभी तक लगाए गए सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अदालत में दोष सिद्ध होना बाकी है।

साइबर अपराधी आम तौर पर निवेशकों को कम समय में बंपर मुनाफे का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाते हैं। इस मामले में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाए जाने की आशंका है। जिसके चलते एसटीएफ अब कंपनी की स्थापना से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की गहराई से पड़ताल कर रही है। लखनऊ पहुंचने के बाद एसटीएफ, राठौर से गहन पूछताछ करेगी, जिससे इस लगभग तीन हजार करोड़ रुपए के नेटवर्क से जुड़े कई अन्य अहम खुलासे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

जर्जर यात्री प्रतीक्षालय तोड़ा, अब दुकानें बनेगी या सुविधा घर

माही की गूंज, पेटलावद।

यहां नगर के गांधी चौक के समीप पेटलावद-रायपुरिया मार्ग पर स्थित पुराना जर्जर यात्री प्रतीक्षालय बुधवार को नगर परिषद के अमले ने तोड़ दिया। उक्त प्रतीक्षालय काफी पुराना हो चुका था और विगत दिनों एक पिकअप वाहन इसके मुख्य पिल्लर से टकरा गया था। जब से इस प्रतीक्षालय की हालत दयनीय हो चली थी ओर नगर परिषद ने इसको बंद कर दिया था। अब नगर परिषद ने इस प्रतीक्षालय को तोड़ दिया है साथ ही नई बहस भी शुरू हो गई है कि इस भवन के स्थान पर नगर परिषद वापस यात्री प्रतीक्षालय बनाएगी या दुकानें निकाल कर नीलाम करेंगे। जबकि यहां एक जर्जर सुविधा घर भी है जिसको तोड़ कर नया सुविधा घर बनाए जाने की आवश्यकता है। अब नगर परिषद में चल रही नूरा कुश्ती के बीच उक्त खाली हुई भूमि एक बार फिर विवादों में पड़ कर ऐसी ही रह सकती है।

पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष 'बाऊजी' के नाम से प्रसिद्ध श्री भट्ट का निधन

माही की गूंज थांदला।

थांदला क्षेत्र से लेकर जिले व प्रदेश तक बाऊजी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले सरल व्यक्तित्व के धनी, जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय समाजसेवी एवं एक अच्छे वक्ता वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश भट्ट के भाई व पत्रकार अक्षय भट्ट के पिता नारायण भट्ट का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही थांदला नगर सहित पूरे जिले के राजनीतिक, सामाजिक, सहकारिता एवं पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

सहज, सरल एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी नारायण भट्ट ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों को आज भी नगरवासी याद करते हैं। इसके अलावा वे कृषि उपज मंडी एवं विपणन सहकारी संस्था के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आदिवासी कल्याण और क्षेत्र के विकास से जुड़े अनेक कार्यों में सक्रिय रूप से सहभागी रहे।

उन्नत कृषक के रूप में भी बाऊजी की अलग पहचान थी। धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी विशेष रुचि रही। उन्होंने अंचल में आयोजित अखिल भारतीय रामायण मेले के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए क्षेत्र में भक्ति और धार्मिक चेतना की धारा प्रवाहित की।

अंतिम यात्राः उमड़ा जनसैलाब

नारायण भट्ट 'बाऊजी' की अंतिम यात्रा में समाजसेवी, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। उनका अंतिम संस्कार नौगावां नदी तट पर किया गया। उनके पुत्र अक्षय भट्ट एवं आशीष भट्ट सहित भाई एवं वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश भट्ट ने अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की।

राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक

बाऊजी के निधन का समाचार मिलते ही प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, विधायक वीरसिंह भूरिया, विक्रांत भूरिया, जिला

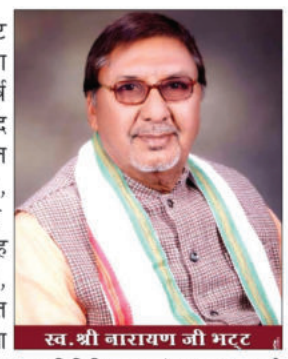

स्व.श्री नारायण जी भट्ट

पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत भाबर, पूर्व विधायक कलसिंह भाबर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पणदा सहित पत्रकारगण एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों ने दिवंगत नारायण भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नारायण भट्ट 'बाऊजी' का निधन क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके सहज व्यवहार, सामाजिक सरोकारों, और जनसेवा के कार्यों को लंबे समय तक याद किया जाएगा।

गूंज की खबर के बाद बीईओ ओझा को हटाया, नितिन परमार को मिला प्रभार

माही की गूंज, पेटलावद।

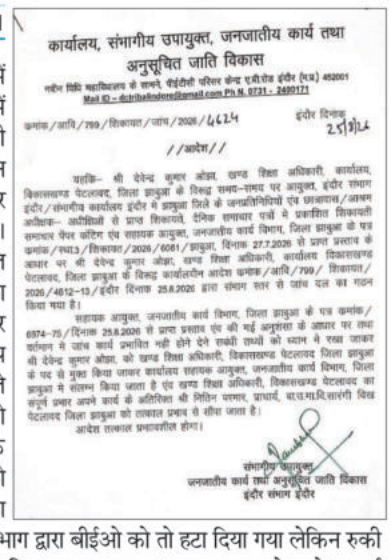

कार्यालय, संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास

गूंज के पिछले अंक में जनजाति कार्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा रोकी हुई वेतन वृद्धि का भुगतान करने के मामले में खबर प्रकाशित की गई थीं। खबर के बाद जनजाति कार्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया ओर लगातार शिकायतों ओर विभागीय कार्य में लापरवाही चलते बीईओ देवेंद्र ओझा को हटा दिया गया। उनके स्थान पर नितिन परमार को खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभारी बनाया गया है। विभाग द्वारा बीईओ को तो हटा दिया गया लेकिन रुकी वेतन वृद्धि का भुगतान के लिए प्रकरण बनाकर भुगतान करवाने वाले प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद पर अभी भी मेहरबान है। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई की आधिकारिक सूचना नहीं आई है।

तपस्वी के घर पहुंची समिति

माही की गूंज, रायपुरिया।

धार्मिक एवं तपस्वी श्रावक अनिल मुथा की 28 उपवास की तपस्या गतिमान है। उनकी इस कठिन तपस्या की अनुमोदना करने के लिए महावीर समिति पेटलावद का प्रतिनिधिमंडल रायपुरिया पहुंचा। महावीर समिति के सदस्यों ने अनिल मुथा के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें साल-माला पहनाकर उनकी तपस्या की भावपूर्ण अनुमोदना की। इस दौरान उपस्थित सभी धर्मप्रेमीजनों ने तपस्वी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके तप की अनुमोदना की।

टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों का जंतर मंतर पर होगा धरना प्रदर्शन

माही की गूंज, पेटलावद।

सरकार ओर शिक्षकों के बीच टीईटी की परीक्षा को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर परीक्षा देने की बात कर रही तो शिक्षक संघ इस परीक्षा का विरोध अब बड़े स्तर तक करने जा रहे है।

तमिलनाडु विधानसभा ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से पूरी तरह और स्थायी छूट देने का एक प्रस्ताव पास किया है। जिसके बाद से इस परीक्षा के दायरे में आ रहे शिक्षकों को एक उम्मीद बंधी है ओर शिक्षक संगठनों ने सरकार से अपनी मांगो को लेकर की जारी लड़ाई को तेज करने का निर्णय लिया है। बुधवार को स्थानीय डाक बंगला परिसर पेटलावद में अध्यापक संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें टीईटी परीक्षा के विरोध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि, टीईटी परीक्षा हर हाल में निरस्त करवाने की बात कही। इसके लिए आगामी 30 अगस्त को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में ब्लॉक से अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील की गई।

अध्यापक शिक्षक संयुक्त संघ के कैलाश वसुनिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, यह हमारे रोजी-रोटी के लिए संकट की घड़ी है, जिसके लिए हम सभी को एकता की ताकत दिल्ली के गलियारों में दिखाना होगा। उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि, 2010 से पूर्व सेवारत समस्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अतिआवश्यक है।

रविदास जन्म जयंती पर कलश यात्रा का स्वागत

माही की गूंज, काकनवानी।

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर शासन द्वारा चलाए जा रहे वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल काकनवानी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सामाजिक समरसता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काशी की पवित्र धरा से लाए गए कलश की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात महाकाल की आरती एवं संत रविदास महाराज का नमन-वंदन किया गया। उपस्थित अतिथियों एवं प्रबुद्धजनों ने संत रविदास जी के जीवन, चिंतन, सामाजिक समरसता तथा मानव कल्याण की विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज को समानता, सद्भाव, परिश्रम, सेवा और मानव कल्याण का संदेश दिया। उनका अमर संदेश ÷मन चंगा तो कठौती में गंगा÷ आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्मन की शुद्धता और सदाचार का मार्ग दिखाता

कार्यक्रम का संचालन मसूल डामोर द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल पांचाल सहित कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मंडल मोर्चा महामंत्री उमेश मकन डामोर द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

फसल को नुकसान पहुंचा कर मोटर चोरी कर गए चोर

माही की गूंज, करवड। खेत में फसल तोड़कर पानी की मोटर ले गए चोर। पेटलावद थाना क्षेत्र के करवड़ चौकी के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में मनीष पिता रघुनाथ सोलंकी के खेत पर खड़ी फसल मक्का और कपास को हाथ और पांव से तोड़कर खेत में ही फेक कर नुकसान पहुंचा दिया है। मनीष सोलंकी ने बताया कि, शरारती तत्वों के द्वारा गांव का माहौल खराब किया जा रहा है। वही खेत के पास तलाव में रखी पाच हॉर्स पावर की मोटर भी चुरा ले गए। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। करवड़ पुलिस चौकी पर शिकायतकर्ता मनीष पिता रघुनाथ सोलंकी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है एवं चौकी प्रभारी से आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की।

खुले जंगल फिर लापता हुई मादा चीता

श्योपुर। मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से मादा चीता निर्वा के एक बार फिर लापता होने की खबर सामने आई है। बीते एक सप्ताह से चीता निर्वा की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। हालांकि कूनो के अफसर चीता के लापता होने की बात से इंकार कर सभी चीतों के सुरक्षित होने का दावा कर रहे है। बताया जा रहा है कि निर्वा मॉनिटरिंग टीम की पकड़ से बाहर है। उसके कॉलर से सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिल रहा है और उसकी सटीक लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। इसके बाद वन विभाग ने पांच टीमें बनाकर 100 से ज्यादा वनकर्मियों को तलाश में लगाया है। ड्रोन और कैमरों की मदद से भी संभावित क्षेत्रों में सर्च किया जा रहा है।

वन विभाग के अनुसार निर्वा के कॉलर से पिछले सात दिनों से सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बीएचएफ सिग्नल से तलाश की बात कही जा रही है, जिसकी प्रभावी रेंज करीब 500 मीटर है।

फिलहाल निर्वा के साथ किसी अनहोनी की पुष्टि नहीं हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता और वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निर्वा कई दिनों से कूनो से लापता है और वनकर्मी उसकी तलाश में जुटे हैं। कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने आजतक को फोन कॉल पर सिर्फ इतना ही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है,बल्कि कूनो में सभी चीते सुरक्षित हैं।

आदिवासी छात्राओं के भोजन का बेहतर बजट फिर भी गुणवत्ताहीन भोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रदेश के छात्रावासों में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण विद्यार्थी पढ़ाई करने के स्थान पर आंदोलन करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। वही प्रशासन आश्वास दे कर उनको वापस अपने होस्टल भेज रही है। सरकार चिंता से दूर बेखबर है क्योंकि वह इस विश्वास में है कि, सरकार द्वारा छात्रावासों में भोजन के लिए बजट का आवंटन अच्छाखासा किया जा रहा है।

बीते दिनों प्रदेश के बहुत से स्थानों पर छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी, कन्या छात्रावास की छात्राएं भी सड़को पर आंदोलन की राह पर चलते दिखाई दिए। क्योंकि वे अपने छात्रावासों की मुलभूत व्यवस्थाओं और अन्य समस्या को लेकर परेशान थी। विशेष रुप से विद्यार्थी, उनको मिलने वाले घटिया भोजन की शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के ध्यानाकर्षण के लिए अपने छात्रावास से निकले थे। घटिया व गुणवत्ताहीन भोजन को लेकर सड़क पर आने वाले विद्यार्थियों की स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि सरकार की तरफ से प्रति छात्र प्रति माह 1740 रुपए भोजन की कच्ची सामग्री के लिए दिए जाते हैं। जिसमें तेल, मसाले, सब्जी, ईधन शामील है। साथ ही इसके गेहु, चावल अलग से आवंटीत किए जाते हैं। अब सरकार द्वारा आवंटित 1740 रुपयों का प्रति छात्र प्रति माह पूर्ण निष्ठा के साथ उपयोग किया जाता है तब भोजन की इतनी खराब स्थिति नहीं बनना चाहिए कि, छात्र-छात्राओं को सड़को पर आने की आवश्यकता पड़ जाए।

छात्रावास में बजट की कमी है तब अधिक्षक अपने उच्च अधिकारियों को समस्या बता सकते हैं, परंतु इस तरह के समाधान वाले कदम सामने नहीं आते। तब निश्चित रुप से अनेक आदिवासी छात्रावासों में निगरानी तंत्र में कमजोरी या भ्रष्ट्राचार करने वालों के हाथ ज्यादा मजबूत हुए होगें।

आंकड़ो के अनुसार प्रदेशभर में सभी श्रेणियों के कन्या छात्रावास को मिलाकर कूल स्वीकृत सीटों की संख्या 81,804 है और आदिवासी क्षेत्र में 1,544 कन्या छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विभाग द्वारा 1083 आश्रम-छात्रावास भी अलग से संचालित किए जाते हैं, इसमें 80 हजार विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। 47,429 करोड़ रुपए का प्रावधान है आदिवासी कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 के राज्य बजट में, फिर भी घटिया भोजन के लिए छात्र-छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अच्छी खासी सहायता के बाद भी भोजन में गड़बड़ी, खाने में कीड़े निकलना, दूषित पेयजल, गुणवत्ताहीन भोजन की गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में सभी छात्रावासों को मिलाकर डेढ़ लाख छात्र-छात्राएं आवासीय शिक्षा ले रहे हैं। इन पर 14.23 करोड़ रुपए प्रतिमाह केवल भोजन सामग्री जैसे तेल, मसाला, सब्जी पर खर्च किया जाता है। यह राशि प्रतिवर्ष लगभग 142.34 करोड़ रुपए बैठती है। प्रदेश के बजट को देखे तो वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आदिवासी कल्याण के लिए 47,429 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य बजट का 25.8 प्रतिशत है।

अच्छे बजटिय प्रावधान के बाद भी व्यवस्थागत लापरवाही के कारण छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालाघाट में अव्यवस्था और वार्डन अधिक्षिका के खराब व्यवहार से तंग आकर छात्राओं ने बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया और शिकायत दर्ज करवाई। शहडौल के आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राएं घटिया भोजन और अव्यवस्था से परेशान होकर 8 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया उसके बाद छात्राएं वापस लौटी। छींदवाड़ा और खंडवा में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई। झाबुआ-आलीराजपुर में भी गुणवत्ताहीन भोजन की शिकायतें बहुत बार हो चुकी है।

आम तौर पर सरकारी संस्थानों पर अव्यवस्था की एक बड़ी वजह होती है सरकारी बजट की कमी होना। परंतु आदिवासी छात्रावासों के मामले में तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दी जा रही है। इस पर क्या प्रशासनिक तंत्र विफल है या ऐसा कौन सा भ्रष्ट तंत्र सक्रीय है जो बच्चों के भोजन का पैसा अपनी जेब में भरकर नई सुविधाए प्राप्त कर रहा है।

सरकार को इस पर विशेष रुप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली लापरवाही का परिणाम कूल मिलाकर सरकार को ही भूगतना है। सरकारी छात्रावास की छात्राएं और छात्र यदि आंदोलन के लिए निकलेंगें तो इसमें साख सरकार की ही गिरेगी। क्योंकि विपक्ष यही मुद्दा बनाएगा की सरकार बच्चों के मुंह में निवाला गुणवत्ताविहीन डाल रही है जिस कारण से बच्चों के मानसिक और शारिरीक विकास पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। आदिवासी छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता पर प्रश्न है तो सरकार को अपने तंत्र को सक्रीय करते हुए निगरानी तंत्र को शक्ति प्रदान करना चाहिए। ताकि पढ़ाई के अच्छे माहौल को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के लिए सड़क पर न उतरना पड़े।

रिकेश बैरागी

अधिकारियों के अनुसार निगरानी के लिए अधिक्षक से लगाकर अधिकारी स्तर की व्यवस्थाएं बनी हुई है, पालक शिक्षक संघ भी है। पूरे प्रदेश में इसकी बैठके लगातार की जा रही है। कहीं भी थोड़ी बहुत भी कमियां पाई जा रही है वहां उनका तुरंत समाधान करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो ऐसी स्थितिया सामने क्यो आ रही है।

किसी भी सभ्य समाज में व्यक्ति को अच्छा भोजन नहीं मिल पाना उस समाज की सबसे बड़ी विफलता ही है। ऐसे ही विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देना किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शासन और प्रशासन का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को ऐसी चिंता से मुक्त किया जाए और उनके लिए पढ़ाई का माहौल अच्छा उपलब्ध करवाया जाए।

बहरहाल भोजन की गुणवत्ता से शासन-प्रशासन भ्रष्ट्राचार कर समझौता करेगी तो छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रदेश के भावी भविष्य है उनपर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ सकती है। सरकार अनुकूलता चाहती है तो विद्यार्थियों को भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की समस्या से दूर उन्हें उचित सुविधाएं देकर उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।

खवासा में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई या फिर ढकोसला...?

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सोलंकी

खवासा सहित क्षेत्र की ही बात करें तो यहां 40 से अधिक अवैध चिकित्सक इलाज के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तथा जिला अधिकारी भी इन्हें चिकित्सक मानने से इनकार कर रहे हैं। फिर भी यह फर्जी चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार के मुंह पर फर्जी उपचार के साथ तमाचा मार रहे हैं। वहीं फर्जी लेब भी अनियमिताओं के साथ खवासा में संचालित हो रही है।

वर्तमान में मौसमी बीमारी चरम पर है वहीं मंगलवार को जिले के डीएचओ डॉक्टर हेमंत देवड़ा के साथ 4 सदस्यी टीम ने यहां चल रही दो लैबोरेट्री पर कार्रवाई करते हुए जांच की गई। जहां कई तरह की अनियमिताएं पाए जाने पर कार्रवाई के नाम पर दोनों लैबोरेट्री को सील कर देने की बात कही गई। तत्पश्चात उक्त कार्रवाई के बाद स्थानीय फर्जी चिकित्सकों में जिनको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के आने की जानकारी मिली जिस पर अपने फर्जी क्लीनिक बंद कर रफू-चक्कर हो गए।

लेकिन जिसका क्लिनिक खुला था फर्जी चिकित्सक शंकर मंडल व गुप्ता मेडम के क्लीनिक पर जाच टीम पहुंची लेकिन उक्त स्वास्थ्य टीम की कार्रवाई कम और ढ़कोसला ज्यादा दिखाई दिया। उक्त स्वास्थ्य टीम ने यहां का न कोई पंचनामा बनाया न कोई मेडिसिन जब्त कि ओर न ही कोई कार्रवाई की।

स्वास्थ्य विभाग की जाच टिम माही की गूंज को जानकारी देते हुए।

पाटीदार लैब जहा लैब का कोई नाम अंकित नही है कार्रवाई के बाद बन्द है।

माही की गूंज प्रतिनिधि ने उक्त कार्रवाई के बाद डीएचओ डॉक्टर हेमंत देवड़ा से बात की तो बताया, पाटीदार लैब एवं श्योर लैब दोनों लैब पर निरीक्षण करने पर कई अनियमिताएं सामने आई और कई स्वास्थ्य विभाग संबंधी प्रोटोकॉल को फोलो नहीं किया गया था जिसके चलते दोनों लैबोरेट्री को सील कर दिया गया है।

साथ ही अवैध चिकित्सकों के संबंध में जब माही की गूंज प्रतिनिधि ने सवाल किया कि, यह अवैध चिकित्सक कार्रवाई के तुरंत बाद ही अपना अवैध उपचार चालू कर दिया जाता है? जिस पर डॉक्टर हेमंत देवड़ा ने सवाल को पूरी तरह से सही बताया और उक्त फर्जी चिकित्सकों के संबंध में कहा कि, उक्त फर्जी उपचार करने वाले को चिकित्सक कहना गलत होगा। यह चिकित्सक नहीं है और यह जानलेवा उपचार करते हैं इनके विरुद्ध सतत् कार्रवाई की जाएगी।

बीएचएमएस डॉक्टर के संबंध में कहा कि, यह डिग्रीधारी चिकित्सक सिर्फ होम्योपैथी इलाज कर सकते हैं एलोपैथी इलाज नहीं कर सकते हैं।

उक्त स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम खवासा से जाने के बाद ही पुनः सभी फर्जी क्लिनिक शुरू हो गए। वहीं पाटीदार लैब जहां लैब का कोई नाम अंकित नहीं है कार्रवाई के बाद बुधवार शाम समाचार लिखे जाने तक बंद थी। वहीं अन्य श्योर लैब का मेडिकल स्टोर चालू था।

उक्त फर्जी क्लिनिक, स्वास्थ्य टीम के जाने के बाद शुरू होने पर ग्राम में चर्चा चलने लगी कि, स्वास्थ्य जांच टीम कार्रवाई करने आई थी या ढकोसला...? चर्चा होने लगी कि, अभी फर्जी चिकित्सकों की सीजन चल रही है और जांच के नाम पर पहुंची स्वास्थ्य टीम की यह कार्रवाई महज फर्जी चिकित्सको को मोटा लिफाफा उन्हें पहुंचाने का संदेश देकर गई है। इसी संदेश के चलते जांच टीम जाने के बाद ही फर्जी चिकित्सकों ने अपने-अपने लिफाफे भरकर पहुंचाने की बाद के साथ सभी फर्जी चिकित्सको ने अपने क्लीनिक स्वास्थ्य टीम जाने के साथ ही खोल दिए गए।

सिविल अस्पताल में महिला मरीज के उपचार को लेकर विवाद, जांच का आश्वासन

माही की गूंज, थांदला।

स्थानीय सिविल अस्पताल में महिला मरीज के उपचार को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार, महिला मरीज दर्द से परेशान थी और चिकित्सकीय जांच के लिए उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। लगभग 25 मिनट बाद नंबर आने पर महिला विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. प्रदीप भारती द्वारा मरीज की जांच करने से इनकार किए जाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि, चिकित्सक ने यह कहते हुए जांच करने से मना किया कि, वे केवल प्रसूति संबंधी कार्य देखते हैं। इस दौरान अस्पताल में स्थिति को लेकर कुछ देर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर डॉ. मनीष दुबे ने तत्काल मरीज को देखा तथा आवश्यक उपचार शुरू करवाया।

जांच का आश्वासन

इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई तो मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। अब देखना यह है कि, विभागीय जांच में पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है और जिम्मेदारी किसकी निर्धारित होती है। मामले मे अधिकारियों द्वारा बताया गया कि, माह की 25 तारीख को संबंधित चिकित्सक की ड्यूटी कार्य निर्धारित होने के कारण सामान्य मरीजों को देखने का विषय अलग था। हालांकि, मरीज पक्ष का सवाल है कि यदि उस समय सामान्य मरीजों की जांच नहीं की जानी थी तो चिकित्सक के कक्ष में बैठने का औचित्य क्या था और आम मरीजों को इस व्यवस्था की जानकारी कैसे होती। फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मरीजों एवं उनके परिजनों की मांग है कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समय पर उचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अंतिम सोमवार भगवामय : माही से मधुकन्या तक पहुंचे कावड़िए, भोलेनाथ की सवारी भ्रमण के लिये निकली

संतो की सभा।

पेटलावद।

भेरूगढ़ माही नदी से बामनिया आती कावड़ यात्रा में महिलाओं का हुजूम।

माही की गूंज, पेटलावद।

सावन माह के पावन अवसर पर अंतिम सोमवार को पूरे अंचल में भगवा ब्रिगेड की धूम रही। यहां बामनिया के समीप माही नदी से लेकर श्रृंगेश्वर धाम मधुकन्या नदी तक अलग-अलग मंडल द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। जिसमें हजारों कावड़ियों ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अलग-अलग शिवालयों में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धर्म लाभ लिए। श्रावण सोमवार के अंतिम सोमवार के चलते कई गांवों में भोलेनाथ की सवारी नगर में भ्रमण करवाई गई। प्रतिवर्ष बामनिया में अंतिम सोमवार को निकलने वालीं कावड़ यात्रा में इस एक हजार से ज्यादा कावड़िए शामिल हुए। यहाँ सभी कावड़ यात्री सुबह ट्रेन से भेरूगढ़ स्थित माही नदी पहुंचे और वहां से जल भर के लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बामनिया स्थित भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंच कर भगवान का जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान कावड़ियों का जगह-जगह स्वागत हुआ ओर फल,खिचड़ी, दूध का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने यात्रा में भाग लिया। शाम को शिव मित्र मंडल द्वारा पूरे ग्राम में भोलेनाथ को भ्रमण करवाया ओर शिव यात्रा निकाली जिसमें बैंड,ढोल, बच्चों के मनोरंजन के लिए गोरिल्ला, डमरू बजाने वाली टीम, डीजे आदि शामिल रहे।

ग्राम पंचायत बामनिया सरपंच रामकन्या मखोड़, उप सरपंच बृजभूषण सिंह परिहार, अजय जैन, सोहन डामर सहित कई लोगों का विशेष सहयोग रहा।

पेटलावद में जुटी रिकॉड तोड़ भीड़,

जेसीबी से हुई फूलों की वर्षा

सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर रमेश सोलंकी मित्र मंडल के तत्वावधान में भव्य समरसता कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो अब अपनी सफलता के आठवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन ने पूरे अंचल को आस्था के सागर में डुबो दिया। पेटलावद क्षेत्र पूरी तरह शिवमय नजर आया।

लाडकी नदी तट से कावड़ यात्रा

यात्रा की शुरुआत ग्राम रामगढ़ स्थित लाडकी नदी के पावन तट से हुई। यहां विधि-विधान से पूजन के पश्चात कावड़िए पवित्र जल लेकर पैदल पेटलावद स्थित ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। हजारों की संख्या में शामिल शिवभक्तों ने भगवा वस्त्र धारण कर हाथों में कांवड़ उठाई थी। ढोल-ढमाकों की थाप, डीजे की धुन और गूंजते धार्मिक नारों ने पूरे यात्रा मार्ग को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान विभिन्न रूपों में सजे स्वांगधारी कांवड़िए भी यात्रा का विशेष आकर्षण रहे, जिन्हें देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ एकत्र हुई।

नीलकंठेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और महाप्रसादी

यात्रा के पेटलावद पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में कावड़ के पवित्र जल से भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां सभी ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक माहौल को और अधिक जीवंत बनाने के लिए प्रसिद्ध गुजराती गायक विक्रम चौहान ने अपनी सुमधुर आवाज में मंत्रमुग्ध कर देने वाले भजनों की प्रस्तुतियां दीं।

धर्म सभा और संतों का मार्गदर्शन

यात्रा के पश्चात एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनान्द गिरी जी महाराज (श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा) ने अपने ओजस्वी संबोधन में श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दिलाया। महाराजश्री ने कहा कि, हिंदू समाज को आपसी दूरियां मिटाकर सदैव एक-दूसरे का साथ देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष हेमंत भट्ट ने समरसता कावड़ यात्रा के सफल आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया। मंच पर 108 श्री जितेनानंद जी महाराज भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनके सान्निध्य ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। आयोजक जनपद पंचायत पेटलावद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि, इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ ग्रामीण अंचल में सामाजिक समरसता और सनातन धर्म के प्रति जनजागृति फैलाना है। मंच संचालन सुखराम मोरी ने किया, आभार संजय कहार ने माना। अंत में महाप्रसादी वितरण के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन का समापन हुआ।

छात्रावास में संदिग्धों की गतिविधियां

माही की गूंज, रतलाम। विरियाखेड़ी स्थित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पीजी आदिवासी छात्रावास में गत 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात 1 बजे कुछ अज्ञात बदमाश घुसे और वहां दहशत फैलाने का काम किया। रात में विद्यार्थियों को इसका पता नहीं चला किंतु सुबह इसकी जानकारी लगी। बाद में सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के कुछ और साथी भी हॉस्टल के बाहर दिखे। दो दिन तक छात्रावास प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार की शाम सात बजे हॉस्टल के छात्र औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंच गए और एफआइआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना प्रभाकी डीएसपी गायत्री सोनी ने उनकी बात सुनी और कहा कि आप लोग चाहे तो अभी एफआइआर करवा ले या फिर आवेदन देकर जांच करवाए जिसे नामजद केस दर्ज किया जा सके। फिलहाल छात्रावास अधीक्षक गोकुल सिंह धारवे की तरफ से थाने पर आवेदन दिया गया है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ विद्यार्थी एफआइआर दर्ज करवाने पर अड़े रहे। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी दिनेश माल ने बताया कि घटना के बाद विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लेने पर छात्रों को थाने पर आना पड़ा। करीब दो दर्जन छात्र माल के साथ मंगलवार की शाम को थाने पहुंचे। छात्रों का कहना है कि पांच-छह लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर छात्रावास के अंदर देर रात आए थे। उनके हाथों में हथियार, लाठी और लोहे की रॉड भी थी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि इनके 15-20 साथी हॉस्टल के गेट के बाहर खड़े हुए थे।

बयानों में विरोधाभास

छात्रों और अधीक्षक के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि धारदार हथियार लेकर आए थे और दरवाजों पर मार रहे थे। दूसरी तरफ अधीक्षक का कहना है कि कोई तोडफ़ोड़ नहीं हुई। संभवत-दहशत फैलाने के लिए ये लोग आए थे।

देर रात अज्ञात पर केस दर्ज

पीजी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने रात में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनके साथ अधीक्षक गोकुलसिंह धार्वे भी थे। अधीक्षक धार्वे की तरफ से थाने में अज्ञात की गतिविधियों का आवेदन दिया गया। इसके बाद भी छात्र एफआइआर दर्ज करने पर अड़े रहे। इस पर थाना प्रभारी डीएसपी गायत्री सोनी ने छात्र की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ दहशत फैलाने और अनधिकृत रूप से छात्रावास में प्रवेश का केस दर्ज किया।

विरियाखेड़ी स्थित पीजी हॉस्टल में गत 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को कुछ अज्ञात बदमाशों की संदिग्ध गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया। वे मंगलवार की शाम को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंचे। देर रात विद्यार्थियों की तरफ से अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

गूंज असर: फिल्टर वाटर प्लांट चोरी का खुलासा

13 से 17 साल के 3 नाबालिग पकड़ाए, 15 हजार का माल बरामद, बाहरी लोगों के सत्यापन पर उठे सवाल

माही की गूंज, बामनिया।
हरिश भटेवरा

ग्राम पंचायत बामनिया के लाड़की बैराज स्थित पानी सप्लाई प्लांट पर लगातार हुई तीन चोरियों का बामनिया पुलिस ने माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने के बाद आखिरकार खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को पकड़ा है, जिनकी उम्र महज 13, से 17 साल बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी बामनिया के नाथ मोहल्ला के निवासी हैं। पूछताछ में सामने आया है कि, इनमें से दो आरोपी 9वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नशे और आवारागर्दी की लत में चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे।

केसे देते थे वारदात को अंजाम...?

पुलिस पूछताछ में बाल अपचारियों ने बताया कि, वे रात के समय सुनसान लाड़की बैराज स्थित प्लांट पर जाते थे। वहां से पानी सप्लाई मोटर की केबल काटकर ले जाते थे, इसके बाद केबल को सुनसान जगह पर जलाते थे, ताकि ऊपर का प्लास्टिक जल जाए और अंदर से कॉपर (तांबा) और एल्युमिनियम निकल जाए। फिर इस तांबे और एल्युमिनियम को कबाड़ी को बेचकर मिलने वाले पैसों से अपना खर्च चलाते थे।

तीसरी बार उन्होंने पाइप चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वजन ज्यादा होने से ले जा नहीं पाए और तोड़कर छोड़ गए थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर छुपाया हुआ करीब 15 हजार रुपए कीमत का चोरी किया गया केबल और तार बरामद किया है।

पुलिस ने चोरी का माल किया जप्त।

बतादे कि, फिल्टर वाटर प्लांट में बार-बार हो रही चोरी का मामला माही की गूंज ने अपने पिछले अंक में प्रमुख्ता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद पुलिस हरकत मे आई और मामले का खुलासा किया।

बाहरी लोगों के सत्यापन का मुद्दा गंभीर

इस चोरी की घटना के बाद बामनिया में बाहरी लोगों के सत्यापन का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बामनिया में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आए लोगों का आना-जाना लगा रहता है। जानकारी के अनुसार पेटलावद रोड स्थित एक कॉलोनी में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से आए लोग कपड़े बेचने का व्यवसाय कर अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान से आने वाले पानी-पतासे, पलंग-कुर्सी बेचने वाले और गर्मियों में बड़ी संख्या में आइसक्रीम बनाकर बेचने वाले लोग भी कुछ महीनों के लिए यहां मकान किराए पर लेकर रहते हैं। चर्चा है कि, ऐसे कई मकान मालिक किराए पर मकान देने से पहले पुलिस चौकी में किरायेदार का सत्यापन नहीं कराते हैं। बिना सत्यापन के अज्ञात लोगों के रहने से क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस पानी सप्लाई प्लांट की चोरी में लोकल नाबालिगों का हाथ सामने आया है, फिर भी कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। ग्रामवासियों का कहना है कि, पुलिस को समय-समय पर कॉलोनियों में जाकर बाहरी किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाना चाहिए, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके।

पुलिस-मीडिया समन्वय पर भी सवाल

बामनिया में पुलिस और पत्रकारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को लेकर भी उदासीनता देखने को मिल रही है। पूर्व चौकी प्रभारी द्वारा पत्रकारों को समय पर सूचना देने के लिए पुलिस-पत्रकारगण सूचना नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप में समय-समय पर घटनाओं की जानकारी और प्रेस नोट जारी किए जाते थे। लेकिन पिछले करीब दो वर्षों से यह ग्रुप पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा है। कोई भी सूचना या प्रेस नोट जारी नहीं किया जाता। इससे कई बार महत्वपूर्ण घटनाओं की आधिकारिक जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। पत्रकारों ने मांग की है कि, पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस ग्रुप को फिर से सक्रिय किया जाए।

संपादकीय

जहर बांटते उद्योग

कुछ उद्यमी मुनाफे की अंधी हवस में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ किए बिना ही जलधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बद्दी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां नदियों में ज़हरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बद्दी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निस्संदेह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं हैं। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिकॉर्ड कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बाबत कई बार जांच भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना ट्रीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्युटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व और एंटीबॉयोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं।

दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बहाव की दिशा में बेफिक्री से छोड़ दिया गया। निस्संदेह, यदि यह कचरा नुकसानदायक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारें मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है। यही वजह है कि अभी अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन यह एक हकीकत है कि अज्ञात इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, दोषी होने का सबूत नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि पंजाब और हिमाचल के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मिलकर साझी जांच करें। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चाहिए कि वह इसकी स्वतंत्र रूप से निगरानी करे। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस घटना के बाद बद्दी-सिरसा-सतुलज की पूरी चेन की लगातार निगरानी की जाए। वहीं दूसरी ओर मॉनसून के दौरान अचानक निरीक्षण, अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों की पहचान करना और वैज्ञानिक तरीके से प्रदूषण के असली स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी प्रावधान हो कि बार-बार नियम तोड़ने वाले उद्यमियों पर कड़े आर्थिक दंड लगाए जाएं। उन्हें आपराधिक कृत्य के लिये परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहने को भी कहा जाए। शायद तभी धरती, पानी और हवा को प्रदूषित करने वाले कारोबारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

बीमार मानसिकता से मुक्ति की हो ईमानदार कोशिश

बरसों पुरानी बात है, शायद मध्य प्रदेश की है। परिगणित जाति की एक महिला सरपंच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से मिलने गयी थीं। काम हो जाने के बाद जब वह सरपंच कार्यालय से चली गयीं तो उस अधिकारी ने वह कुर्सी धुलवाकर 'पवित्र' करवायी थी जिस पर परिगणित जाति की महिला बैठी थी! यह समाचार तब कुछ अखबारों में छपा था। कुछ चर्चा भी हुई थी इसे लेकर। पर जल्द ही यह घटना लोग भूल गये। अपने ढंग की अकेली घटना नहीं थी यह। तथाकथित छोटी-जाति वालों के साथ ऐसा घटता रहता है। कभी घोड़े पर चढ़कर बारात ले जाने वाला कथित छोटा जाति वाला कथित उच्च जाति के गुस्से का शिकार बनता है तो कभी किसी स्कूल में छोटी जाति के बच्चों को पृथक बिठाने का समाचार मिलता है। पर हमारी सामाजिक स्मृति में ऐसी घटनाएं बहुत दिन तक नहीं रहतीं। भूल जाते हैं हम कि हमारे तथाकथित समतामूलक समाज में ऐसा भी कुछ घटा है या घट रहा है। नहीं भुलाया जाना चाहिए ऐसी बातों को। इन्हें याद रखना ज़रूरी है ताकि हमें यह अहसास होता रहे कि प्रगति के सारे दावों के बावजूद हमारी सोच कितनी पिछड़ी हुई है।

हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऐसी ही एक शर्मनाक घटना घटी थी, जिसे याद रखा जाना ज़रूरी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ घटी इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं राज्यसभा में दिया था। यह अच्छी बात है कि राज्यसभा में सत्तारूढ़ पक्ष के नेता ने इस प्रकरण की जांच करने का आश्वासन देकर खड़गे जी की पीड़ा पर कुछ मरहम लगाने का काम किया। पर यह पीड़ा सिर्फ खड़गे जी की नहीं है, सिर्फ उनकी ही पीड़ा होनी भी नहीं चाहिए। इस पीड़ा का अहसास उस हर भारतीय को होना चाहिए जो समता और न्याय के आदर्शों में विश्वास करता है, जो यह मानता है कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने हल्द्वानी में घटी इस शर्मनाक घटना का विवरण देते हुए बताया था कि यहां मैदान में उनका भाषण था, उस जगह और उस मंच को गंगाजल से धोकर शुद्ध किया गया था। शुद्धीकरण का आयोजन करने वाले कथित उच्च वर्ण वालों का कहना था कि जहां यह सभा हुई थी, वहां रामलीला का आयोजन होता है। इसलिए हवन करके जगह को शुद्ध किया गया!

इस अस्वीकार्य घटना की जांच कहां तक पहुंची है, पता नहीं। अक्सर ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर भुला दिया जाता है। पर होना यह चाहिए कि फिर जब कुछ ऐसा घटे तो हम यह अनुभव करें कि स्वतंत्रता के अस्सी साल बाद भी हम सामाजिक ऊंच-नीच के अभिशाप को ढो रहे हैं। जिस संगठन पर हल्द्वानी की इस घटना का आरोप है उसके सदस्यों का कहना है कि खड़गे जी की सभा जिस मैदान में हुई थी, वहां रामलीला का आयोजन होता है, उस जगह का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। किसी भी सोचने-समझने वाले विवेकशील व्यक्ति को यह तर्क समझ नहीं आ सकता। कहा यह जा रहा है कि 'शुद्धीकरण' का यह तमाशा चुनावी राजनीति का हिस्सा है। हो सकता है यह आयोजन करने वालों ने चुनावी राजनीति के संदर्भ में यह सब किया हो, पर बात चुनावी राजनीति की ही नहीं है; मामला राजनीतिक टकराव से कहीं ज्यादा उस बीमार मानसिकता का है जो हमें जातियों, वर्गों, वर्णों में बांटती है। जातिगत पूर्वाग्रह कहीं बहुत गहरे तक व्याप्त हैं। हल्द्वानी का यह प्रकरण हमारी सोच पर कुंडली मारकर बैठे इन पूर्वाग्रहों को सामने लाता है। मनुष्यता का तकाज़ा है कि हम इससे उबरें।

राजनीतिक स्वतंत्रता हमने लगभग अस्सी साल पहले प्राप्त कर ली थी, पर अधूरी है यह स्वतंत्रता। आवश्यकता सामाजिक रूढ़ियों से उबरकर एक ऐसे समाज को स्वतंत्र बनाने की है जहां व्यक्ति की नाप-तौल उसकी धार्मिक पहचान और उसकी जाति के आधार पर नहीं हो। इस संदर्भ में हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वह संबोधन याद रखने की आवश्यकता है जो उन्होंने संविधान-सभा की आखिरी बैठक में दिया था। अपने उस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, '26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, पर उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? वह अपनी स्वतंत्रता फिर से खो तो नहीं देगा?' इसी भाषण में उन्होंने यह भी आगाह किया था कि उन्हें जाति और वर्ण जैसे देश के पुराने शत्रुओं की भी चिंता है। उन्होंने कहा था, 'हमें राजनीतिक जनतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना, हमें इसे सामाजिक जनतंत्र भी बनाना होगा। बिना सामाजिक जनतंत्र के आधार के राजनीतिक जनतंत्र नहीं बन सकता। सामाजिक जनतंत्र का मतलब है एक ऐसी जीवन-पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकारती है। ये तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक-दूसरे से पृथक करने का मतलब जनतंत्र के उद्देश्य को ही समाप्त करना होगा... समानता नहीं होगी तो इसका मतलब बहुतों पर कुछ का आधिपत्य होगा और समानता बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति की पहल की क्षमता को नष्ट कर देगी।'

स्पष्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर ही हम राजनीतिक स्वाधीनता को सही मायने में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में जब हल्द्वानी जैसी कोई घटना सामने आती है तो यह सवाल उठता ही है कि छोटी जाति और बड़ी जाति वाली मानसिकता से हम कब और कैसे मुक्त होंगे? बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने 25 नवंबर, 1949 वाले संबोधन में कहा था कि स्वतंत्र भारत में हम विरोधाभासों में जिएंगे। राजनीतिक दृष्टि से हम सब समान होंगे, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम में असमानता होगी। इन विरोधाभासों में हम ज़्यादा नहीं जी सकते। हमें इनसे मुक्त होना ही होगा। इनसे मुक्त हुए बिना हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते। स्पष्ट है, सामाजिक विषमता से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति पानी ही होगी। पर हल्द्वानी जैसी घटनाएं बताती हैं कि जानते-बूझते भी हम सामाजिक विषमता से मुक्त होने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे। आखिर क्यों? इस क्यों का एक उत्तर तो यह है कि हमने जातिगत विषमता को अपनी राजनीति का हथियार बना लिया है। हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष को जिस अपमान का सामना करना पड़ा, उसमें जाति के आधार पर राजनीतिक नफे-नुकसान की गंध आ रही है। राज्यसभा में अपनी पीड़ा को उजागर करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की मनोदशा को समझना मुश्किल नहीं है। कहने को हम कह सकते हैं कि खड़गे भी ऊंची जाति-नीची जाति की राजनीति खेल रहे हैं, पर इससे इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता कि जातियों की गोलबंदी ने एक भारतीय समाज की हमारी प्राथमिकता को कहीं पीछे धकेल दिया है। सवाल सामाजिक बराबरी की लड़ाई में जीतने का है। यह जीत ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना को कब साकार कर सकते हैं जिसमें जाति या धर्म के आधार पर नहीं, भारतीयता के आधार पर यह तय होगा कि कौन सही अर्थों में भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकारी है और कौन नहीं। सही अर्थों में भारतीय कहलाने का अधिकारी वही है जो धर्म या जाति के आधार पर नहीं, देश के प्रति अपनी भावना के आधार पर अपनी निष्ठा को प्रमाणित करे। देश के प्रति अपनी निष्ठा का तकाज़ा है कि हम उस सोच को बदलें, उससे मुक्त हों, जो इंसानों के बीच फर्क करता है।

विश्वनाथ सचदेव

यह काम कानून से नहीं हो सकता। कानून तो हैं हमारे देश में, आवश्यकता इन कानूनों को सम्मान देने की है, अपने आचरण को उनके अनुसार बनाने की है। जब तक जातियों के आधार पर वोट मांगे जाते रहेंगे, जब तक जातियां यह तय करती रहेंगी कि किसे वोट देना चाहिए, किसको नहीं, तब तक हम जातीयता के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। उस दिन हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धीकरण के नाम पर जो कुछ हुआ, वह कुल मिलाकर जातीय शर्म का उदाहरण है। अनुसूचित जाति की किसी महिला का सरपंच बनना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता अपने भीतर यह भाव जगाने की है कि वह महिला पहले इंसान है, फिर कुछ और। कब जागेगा यह भाव?

लापरवाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी

आज सबसे बड़ा सवाल है कि जलभराव के बाद राहत क्यों, संकट आने से पहले तैयारी क्यों नहीं? अधिकांश शहरी जलभराव अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। जिन स्थानों पर हर वर्ष पानी भरता है, उनकी पहचान प्रशासन और नगर निकायों को पहले से होती है। यह भी पता होता है कि किस सड़क पर पानी जमा होता है, किस नाले की क्षमता कम है और कहां प्राकृतिक जल निकासी बाधित है। फिर भी हमारा जोर अक्सर पानी भरने के बाद राहत देने पर रहता है, पानी भरने से पहले समस्या रोकने पर नहीं।

इस वर्ष असम में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का दुख है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा रहता है। केवल भारी बारिश को जिम्मेदार बताकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बाढ़ क्षेत्र पर बढ़ता दबाव, प्राकृतिक जल क्षेत्रों का नुकसान, अनियोजित निर्माण और कमजोर पूर्व चेतावनी व्यवस्था आपदा को अधिक विनाशकारी बना सकती है।

हरियाणा की आर्थिक शक्ति गुरुग्राम और देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में शामिल इस शहर में लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन मानसून आते ही कई बार इसकी तस्वीर बदल जाती है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबती हैं, वाहन घंटों फंसते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है। हर वर्ष नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और जल निकासी के इंतजाम किए जाते हैं। फिर अगले मानसून में वही स्थान दोबारा पानी में दिखाई देते हैं। पानी भरने के बाद पंप लगाना जरूरी है, लेकिन पंप स्थायी समाधान नहीं है। जलभराव के बाद यातायात नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उससे बेहतर है कि यातायात प्रभावित ही न हो। पानी निकालना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि पानी जमा ही न हो।

गुरुग्राम की समस्या को केवल अत्यधिक बारिश कहकर समझना अधूरा होगा। तेजी से बढ़ते निर्माण ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम कर दी है। जहां कभी खाली जमीन, तालाब, हरित क्षेत्र और प्राकृतिक जल मार्ग थे, वहां सड़कें और इमारतें खड़ी हो गई हैं। बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है और पर्याप्त निकासी न मिलने पर सड़कें जलाशय बन जाती हैं। इस समस्या से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और देश के अनेक शहर हर वर्ष सामना करते हैं। हमने शहरों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन पानी के लिए जगह नहीं छोड़ी। तालाब, झील और प्राकृतिक जल क्षेत्र खाली जमीन नहीं, बल्कि शहरों की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था हैं।

सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अधिकारी, ठेकेदार या एजेंसी की लापरवाही से सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और प्राकृतिक जल मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक बड़े शहर का वैज्ञानिक बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि अत्यधिक बारिश में पानी किस दिशा में जाएगा।

मानसून से पहले नालों की सफाई भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सफाई से पहले और बाद की स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाए। हर बड़े जलभराव के बाद केवल पानी निकालने की रिपोर्ट न बने, बल्कि यह भी बताया जाए कि पानी क्यों भरा और अगली बार इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा। शहरों में समय पर बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। भारी बारिश की सूचना पहले मिले, यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाए और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पहले से तैनात हो।

दीपक कुमार शर्मा

गुरुग्राम का जलभराव बताता है कि आधुनिक शहर केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं बनता। आधुनिक शहर वह है जो भारी बारिश के दौरान भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके। बारिश हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जल निकासी की योजना, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, निर्माण पर नियंत्रण, नालों का रखरखाव, पूर्व चेतावनी, विभागों का समन्वय और सार्वजनिक धन में पारदर्शिता हमारे हाथ में है।

अब समय आ गया है कि मानसून के बाद राहत की खबरों के बजाय मानसून से पहले तैयारी की खबरें सुर्खियां बनें। किसी शहर में प्रशासन की असली सफलता यह नहीं कि उसने बाढ़ के बाद कितनी तेजी से पानी निकाला। असली सफलता यह है कि इतनी बारिश के बावजूद शहर डूबा ही नहीं।

नालों पर रोक से ही साफ होगी यमुना

देश में पुण्यदायिनी नदी गंगा के बाद दूसरी प्रमुख नदी यमुना का प्रदूषण चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका कारण 85 फीसदी से ज्यादा प्रदूषण बिना ट्रीट किए घरेलू कचरे और औद्योगिक रसायनयुक्त अपशिष्ट है। यदि दिल्ली सरकार की मानें तो यमुना की सफाई अलग-अलग परियोजनाओं के माध्यम से नहीं, वरन दिल्ली के पूरी सीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव के जरिए की जा रही है। सरकार का मानना है कि यमुना तब साफ होगी जब हर घर सीवर नेटवर्क से जुड़ा होगा।

पहले देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा को लें। मोक्षदायिनी मानी जाने वाली नदी गंगा अपने मायके उत्तराखंड से ही प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट कर चुकी है। साल 1985 से लेकर आज तक गंगा की प्रदूषण -मुक्ति हेतु 42,000 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। गंगा एक्शन प्लान पर शुरू में ही 1,200 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। पर हालात जस के तस हैं।

वहीं अब दिल्ली की यमुना नदी तमिलनाडु की कूवम नदी सहित देश की सबसे प्रदूषित नदी है। उसकी सफाई पर अब तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 5,536 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। यमुना संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर पहले ही लगभग 1,951 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट के तहत दिल्ली जल बोर्ड को 6,485 करोड़ रुपये की राशि दी गई। हाल-फिलहाल में ही दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 4,500 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। यही नहीं, यमुना के जल को साफ करने के साथ-साथ नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए 1,000 करोड़ की परियोजनाओं को दिल्ली सरकार ने और मंजूरी दी है। इसके बावजूद हकीकत में यमुना आजकल गंदगी और दुर्गंध से सड़ रही है।

आज यमुना नदी, सीवेज और कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट से इतनी विषैली है कि सभी प्राणियों और जलजीवों की सेहत के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। यहां तक कि यमुना की मछलियां भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। शोध के अनुसार, यहां की मछलियां खाने से या इसका पानी पीने से हार्मोनल असंतुलन, पाचन तंत्र में सूजन और कोशिकाओं को भारी नुकसान हो सकता है। इसका अहम कारण मछलियों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा का अत्यधिक पाया जाना है।

यमुना के जल में जहरीले रसायनों की बात करें तो पानी में अमोनिया की सीमा अधिकांश एसटीपी को भी बाधित करती है। बीओडी का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है और घुलित ऑक्सीजन का स्तर अक्सर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम होने से जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं, मानव और पशु मल-मूत्र से आने वाले बैक्टीरिया का स्तर सीमा से 32,000 गुना से भी ज्यादा है।

दरअसल, कारखानों और सीवेज के जरिए नदी में आने वाले अमोनिया और फॉस्फेट जैसे रासायनिक तत्व जहरीले झाग बनाते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है, गले में सूजन व संक्रमण भी होता है। वहीं पानी में आये क्रोमियम, सीसा, तांबा और अन्य धातुएं शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को कमजोर करती हैं। ये कैंसर, किडनी तथा लीवर जैसे भयावह रोग की वजह बनती हैं।

यदि राजधानी दिल्ली के 22 किलोमीटर इलाके की ही बात करें तो यमुना अपनी बदहाली की कहानी खुद-ब-खुद बयां करती है। यहां का जल फीकल कोलिफॉर्म, लेड जैसी भारी धातुओं व डिटर्जेंट से इतना प्रदूषित है कि इसके संपर्क में आने से लोग कैंसर, त्वचा रोग, सांस, पेट के संक्रमण, लीवर, तंत्रिका तंत्र आदि गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं।

देश का सुप्रीम कोर्ट नौ साल पहले ही आदेश दे चुका है कि नदियों में शोधन के बगैर सीवेज न बहाया जाए। इसके बावजूद ना राज्य सरकारों पर इसका कोई असर पड़ा, ना ही सीवेज निस्तारण करने वाली एजेंसियों पर कि वे इस मामले पर कारगर कदम उठातीं।

यमुना तभी साफ हो सकती है जबकि उसमें गिरने वाले नालों के प्रदूषित पानी को रोका जाए। लेकिन हकीकत यह कि देश में यमुना ही नहीं, मोक्षदायिनी गंगा सहित तकरीबन चार सौ से अधिक नदियों में सीवेज का गंदा पानी 1,385 से भी ज्यादा गंदे नालों के जरिए बहाया जाता है। ऐसे मामलों में बीते वर्षों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। यमुना को विषाक्त करने में नजफगढ़ और शाहदरा के नालों की अहम भूमिका है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आकर इसमें गिरने वाले नालों का योगदान भी यमुना को प्रदूषित करने में कम नहीं। दिल्ली शासन-प्रशासन के दावे के अनुसार, यमुना की सफाई हेतु आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें मिलने वाले नालों पर विकेंद्रित सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) लगाने की योजना बनाई गई है। 13 डीएसटीपी लगाए जाने हैं।

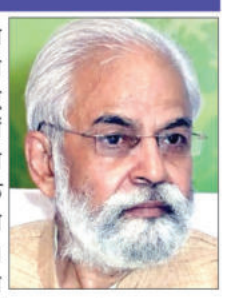

ज्ञानेन्द्र रावत

हालांकि, जब तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आकर यमुना में गिरने वाले नालों की सफाई नहीं होगी, उन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक यमुना की सफाई की उम्मीद बेमानी है। बहरहाल, यमुना की प्रदूषण से बदहाली का क्रम दशकों से जारी है। अब समय है कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ दिल्ली की जनता भी यमुना का प्रदूषण कम करने में सक्रिय व जागरूकता पूर्ण भूमिका निभाए।

स्कूल के रास्ते पर रोज लगने वाले जाम को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा

माही की गूंज, शाजापुर।

ग्राम बमौरी, खेड़ा व आसपास से शाजापुर स्थित सांदीपनि विद्यालय आने वाले जेन अल्फा विद्यार्थियों ने कृषि उपज मंडी में आने वाले वाहनों के कारण मार्ग पर लगने वाले जाम को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कृषि उपज मंडी के पिछले हिस्से के द्वार पर ताला जड़ दिया। जिससे प्याज की बोरियों से भरे वाहन मंडी में प्रवेश नही कर पाए। मौके पर पहुंचीं एसडीएम और टीआई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। जाम और प्रदर्शन के कारण मंगलवार को बच्चों का स्कूल भी प्रभावित हुआ, पढ़ाई का करीब आधा समय बच्चे मंडी द्वार के पास ही खड़े रहे।

बच्चे करीब एक घंटे तक बच्चे रिमझिम बारिश के बीच मंडी गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन करते रहे। उनका कहना था कि मंडी में उपज बेंचने आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली व अन्य वाहन अव्यवस्थित तरीके से रोड पर खड़े होते हैं। जिसके कारण स्कूल बस एबी रोड से अंदर नही आ पाती और उन्हें बस तक पहुंचने के लिए पैदल चलने के साथ अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मौके पर पहुंचीं शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्कले और कोतवाली थाना टीआई संतोष कुमार बाघेला ने बच्चों व अभिभावकों से चर्चा कर समझाइश दी। बावजूद वह नही माने उन्होंने कहा कि रास्ते पर अव्यवस्थित खड़े उपज से लदे वाहनों को व्यवस्थित किया जाए।

स्कूल बस मंडी तक आए तब वह बस में बैठकर ही स्कूल जाएंगे। वह बस में सवार होने के लिए पैदल एबी रोड किनारे तक नही जाएंगे। जेन अल्फा के प्रदर्शन की जानकारी कलेक्टर ऋजु बाफना और एसपी प्रियंका शुक्ला प्रियंका शुक्ला तक भी पहुंचीं। इस पर अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी ली।

बच्चे बोले- कई दिन से थी परेशानी

प्रदर्शन करने वाले बच्चे बोले की कई दिन से यह परेशानी आ रही है। जिसके कारण उन्हें स्कूल जाते और स्कूल से गांव आते वक्त दोनों तरफ से समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार अभिभावक घर पर नही होते तो एबी रोड पर खड़ी बस तक पहुंचना या एबी रोड से गांव तक आने में ज्यादा दिक्कत आती है। सुरक्षा को लेकर भी चिंता रहती है। इसी से परेशान होकर उन्होंने मंडी गेट में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। ताकि जिम्मेदार अधिकारी जागे और उनकी समस्या का समाधान किया जाए।

जल्दी तुलाई के चक्कर में बिगाड़ते हैं कतार

मंडी में विक्रय के लिए आने वाले उपज से लदे वाहन चालक तोल के लिए जल्दी अपनी बारी के चक्कर में वाहनों को आगे-पीछे खड़ा करके पूरा रोड घेर लेते हैं। जिसके कारण ग्रामों की ओर आने-जाने वाले वाहनों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जाम के हालात भी बनते हैं।

सुरक्षा की रहती हैं चिंता

मंडी क्षेत्र में ग्राम बमौरी रोड पर लगने वाले जाम के कारण स्कूल बस एबी रोड किनारे खड़ी हो जाती है। हमें पैदल बस तक पहुंचना पड़ता है। जिसके कारण सुरक्षा की चिंता भी रहती है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है। समस्या के लिए मजबूर होकर प्रदर्शन रास्ता अपनाना पड़ा। - सुहाना पठान छात्रा

पैदल आवागमन में परेशानी, कीचड़ में ड्रेस गंदी

मंडी आने वाले वाहनों को कारण लगने वाले जाम के कारण स्कूल बस एबी रोड किनारे खड़ी हो जाती है। बस तक पैदल आने जाने में समय अधिक लगता है। बारिश के दिनों में रोड पर कीचड़ हो गया है। जिससे ड्रेस भी गंदी हो जाती है। - प्रियांशु छात्र

अस्पताल से नकदी और जेवर से भरा बैग हुआ चोरी

माही की गूंज, मंदसौर।

इंदिरा गांधी जिला अस्पताल के वार्ड से सोमवार को जेवर से भरा बैग चोरी हो गया। महिला तत्काल शहर कोतवाली पहुंची और बताया कि बैग में लगभग चार लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर रखे हुए थे। कीमती सामान से भरे बैग की चोरी को देखते हुए पुलिसकर्मी सतर्क हुए। जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज देखने में जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। इसमें एक श्वान बैग को मुंह में दबाकर ले जाता हुआ दिखा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अस्पताल परिसर में उसे खोज लिया और बेग भी सुरक्षित मिल गया। बाद में महिलाओं बैग में करीब 4 लाख कीमत के सोने-चांदी के आभूषण एवं अन्य कीमती सामान रखा हुआ था।

शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्रसिंह राठौर ने बताया कि लताबाई पत्नी-प्रकाश वाल्मीकि निवासी कयामपुर ने सोमवार को कोतवाली में आकर आवेदन दिया था कि जिला अस्पताल में बेग गुम हो गया है। बैग में लगभग 4 लाख रुपये कीमत सोने-चांदी के आभूषण व अन्य सामान रखा था।

कोतवाली के प्रधान आरक्षक अजय सोलंकी अस्पताल परिसर एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में एक श्वान बेग को लेकर जाता हुआ दिखा। इसके बाद परिसर में खोजबीन कर बेग एवं उसमें रखा कीमती सामान बरामद कर लिया गया। सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य सामग्री आवश्यक कार्रवाई के बाद लताबाई को सुरक्षित सुपुर्द किया गया।

पोस्ट ऑफिस के मकान में दिनदहाड़े चोरी

वहीं मल्हारगढ़ नगर के स्टेशन रोड पर सोमवार सुबह लगभग 11 बजे मकान में घुसे चोर 64 हजार रुपये व जेवरात चोरी कर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह स्टेशन रोड पर पोस्ट आफिस के पास रहने वाले गोपाल मालवीय परिवार सहित किसी कार्यक्रम में गए थे।

कार्यक्रम से लौटे तो घर का मुख्य द्वार खुला था। अंदर जाकर देखा तो समान बिखरा था। गोपाल मालवीय ने बताया सुबह 11 बजे लगभग चोरी हुई हे। मकान से 64 हजार रुपये, जेवरात चोरी हुए है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने छानबीन की। आस-पास के सीसीटीवी कैमरे के फूटेज की भी जांच की जा रही है।

खेत पर सो रहे पति की हत्या, पत्नी की हालत गंभीर

माही की गूंज, मंदसौर।

गरोठ तहसील के ग्राम चांद बड़ी में खेत पर सो रहे दंपती पर जानलेवा हमला कर पति की दर्दनाक हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पत्नी को भी गंभीर घायल कर दिया है। घायल पत्नी को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस अभी हत्या के कारणों की जांच कर रही है। क्योंकि लूट का कोई खास सुराग नहीं मिला है। वहीं मृतक के बेटे का आरोप है कि मां के आभूषण गायब है और लूट के चलते ही हमला कर हत्या की गई है। अब पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मौके पर आखिर हुआ क्या था।

खेत पर पहुंचे तो दोनों लहूलुहान मिले

मिली जानकारी के अनुसार नारायण बंजारा ने शिकायत दर्ज कराई कि मैरे पिता 60 वर्षीय देवीलाल पुत्र गोरीलाल बंजारा और मां 58 वर्षीय भूलीबाई बंजारा प्रतिदिन की तरह सोमवार रात 8 बजे खेत पर सोने गए थे। मंगलवार सुबह 8 बजे स्वजन खेत पर पहुंचे तो दोनों लहूलुहान मिले।

घटना की सूचना मिलते ही गरोठ थाना प्रभारी बलवीर सिंह यादव पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की तो देवीलाल बंजारा की मौत हो चुकी थी उनके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे वहीं पत्नी घायल थी उन्हें तत्काल गरोठ अस्पताल भेजा जहां प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार करने वाले डा. नारायणसिंह ने बताया कि महिला के सिर में गंभीर चोटे लगी है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। मृतक के बेटे नारायण बंजारा ने बताया कि मां के शरीर से सोने-चांदी के आभूषण गायब हैं।

इससे आशंका जताई जा रही है कि बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे और विरोध करने पर उन्होंने माता-पिता पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी बलवीरसिंह यादव ने बताया कि मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें लूट के अलावा कुछ और भी मामला हो सकता है।

एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए है। प्रथम दृष्ट्या यह मामला चोरी की नीयत से पत्थरों से हमला कर हत्या और लूट का नजर आ रहा है। गरोठ पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पीछा कर रोकी कार में मिली 2.495 किलो एमडी ड्रग

माही की गूंज, रतलाम।

कालूखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.495 किग्रा एमडी ड्रग जब्त की है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त काले रंग की क्रेटा कार (आरजे 27-सीपी 3608) भी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान कार सवार चार आरोपित पुलिस को चकमा देकर जंगल में भाग निकले।

थाना प्रभारी शंकरसिंह चौहान ने बताया कि, चौकी मावता के चौकी प्रभारी एसआइ दिनेश राठौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लखन मीणा निवासी भाकरखेड़ी तीन साथियों के साथ काले रंग की क्रेटा कार में एमडी ड्रग लेकर बेहपुर-मंदसौर तरफ से मावता होते हुए रियावन की ओर जाने वाला है। इस पर रानीगांव फंटे पर नाकाबंदी की गई।

कुछ देर बाद कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने गति बढ़ाकर रियावन की ओर वाहन भगा दिया। टीम ने पीछा किया तो आरोपित कार को रियावन से चिपिया होते हुए बिलंदपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर ले गए।

अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर चारों फरार हो गए

रास्ता ऊबड़-खाबड़ होने के कारण बिलंदपुर-चिपिया के जंगल क्षेत्र में कार छोड़कर आरोपित लखन मीणा, चालक और दो अन्य साथी झाड़ियों की ओर भाग गए। पुलिस ने खेतों और झाड़ियों में सर्चिंग की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर चारों फरार हो गए।

संभावित ठिकानों पर दबिश और सर्चिंग की जा रही है

कार की तलाशी में ड्राइवर सीट के नीचे हरे रंग की कपड़े की थैली मिली। इसके अंदर तीन प्लास्टिक थैलियां थीं, जिनमें एमडी ड्रग रखी थी। फरार आरोपितों की तलाश के लिए टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश और सर्चिंग की जा रही है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विजय निनामा, आरक्षक यशवंत जाट, नितीन जोशी, हिम्मतसिंह चौहान, पवन जाट, कमलेश बुनकर, राजपालसिंह, अनिल पाटीदार, लक्ष्मणसिंह एवं महिला आरक्षक योगिता की भूमिका रही।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी में गिरफ्तार

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले में युवा कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल कलेक्टर घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया एवं आसपास की जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुंचे। बस स्टैंड पर सभा का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग सहित भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद सभी कलेक्टर कार्यालय घेराव के लिए आगे बढ़े।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर पहले से ही श्री लेयर बेरिकेडिंग व्यवस्था की गई थी। ऐसे में पहले बेरिकेड्स पर जब सभी लोग पहुंचे तभी फायर ब्रिगेड की मदद से सभी पर वाटर केनन चलाई गई और रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी जब यह लोग आगे बढ़ने लगे तो पुलिस द्वारा सभी को रोका गया। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को पुलिस बस में भरकर गिरफ्तारी कर कर अपने साथ ले गई।

कलेक्ट्रेट घेरने निकले थे युवा कांग्रेसी, पुलिस ने इस्तेमाल किया वॉटर केनन

किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों से जुड़े मुद्दों और सरकार की नीतियों के विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे बस स्टैंड पर आमसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टोरेट का घेराव करने के लिए रवाना हुए। पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। इस दौरान स्थिति नियंत्रित करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने प्रदर्शन को 'युवा कांग्रेस का हल्ला बोल' नाम दिया था। कार्यक्रम 'अन्नदाताओं के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में' नारे के साथ आयोजित किया गया।

छात्रों की आवाज को करना है बुलंद- कांग्रेस जिलाअध्यक्ष

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की आवाज बुलंद करना है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के सामने सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, युवाओं और कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी।

तीन लेयर में की गई थी सुरक्षा व्यवस्था

प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। डिपो क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की व्यवस्था की गई। होमगार्ड लाइन रोड पर भी बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा कलेक्टोरेट के गेट नंबर एक और दो पर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए करीब 300 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे।

भीषण सड़क हादसा, मां-बेटी की मौत

आगर मालवा/ बड़ौद।

उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ग्राम रामाखेड़ी के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश पासिंग अर्टिगा कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक भी रोड किनारे साइड की रैलिंग तोड़ते हुए सड़क से नीचे उतर गया। इस भीषण हादसे में कार में सवार मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

घायलों को शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया

दुर्घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पायलट संदीप गोस्वामी और अमरीश मौके पर पहुंचे तथा घायलों को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ौद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू की।

मृत महिला कार में बुरी तरह फंस गई थी

बताया जा रहा है कि मृत महिला कार में बुरी तरह फंस गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एनएचआई की एम्बुलेंस से दोनों मृत महिलाओं के शव शासकीय अस्पताल बड़ौद लाए गए। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सारिका पति श्यामलाल और छवि पिता श्यामलाल, निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं घायलों में सूरजपाल, सचिन और श्याम निवासी उत्तर प्रदेश बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

पैराडाइज वैली हादसे में 10 वी के छात्र ने बचाई तीन जिंदगियां

माही की गूंज, रतलाम।

सांवलिया रूंडी स्थित पैराडाइज वैली में हादसे से महज कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था। दोपहर 1:41 बजे स्नैपचैट पर आए 43 सेकंड के वीडियो में 16 वर्षीय विशाल भाभर पानी में तैरता नजर आ रहा है। पीछे स्कूल के बच्चे भी पानी में खेलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो खत्म होते ही हालात बदल गए और कुछ ही देर में चीख-पुकार मच गई।

विशाल ने अपनी मां अनीता से कहा- बच्चे डूब रहे हैं, बचाने जाऊं? मां के हां कहते ही वह बिना देर किए बच्चों की ओर पहुंच गया। विशाल सांदीपनि विनोबा स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। उसने पानी में उतरकर पहले एक बच्ची को बाहर निकाला। इसके बाद वह दोबारा पानी में गया और एक अन्य बच्ची तथा छोटे बच्चे को भी बाहर लेकर आया।

तीन लोगों की हुई थी मौत

मालूम हो कि जावरा के त्रिमूर्ति कान्वेंट स्कूल की पिकनिक के दौरान हुए हादसे में संगीत शिक्षक 22 वर्षीय प्रिंस पुत्र तेजकरण मोदी, तिलक नगर निवासी 42 वर्षीय शिक्षक विजय सिंह पुत्र गुरुचंद्र राठौर और ग्राम ऊपरवाड़ा निवासी कक्षा सातवीं के 12 वर्षीय छात्र हर्षित पुत्र समरथ पाटीदार की डूबने से मौत हो गई थी।

बच्चों ने बताया- शिक्षक और अन्य विद्यार्थी अभी पानी में हैं

निजी अस्पताल में नर्स अनीता ने बताया कि विशाल के बच्चों को बाहर निकालने के बाद वहां मौजूद विद्यार्थियों ने बताया कि उनके शिक्षक और अन्य विद्यार्थी अभी पानी में हैं। इसके बाद आसपास के ग्रामीण और अन्य लोग भी पानी में उतरकर तलाश में जुट गए। इसी दौरान अनीता ने अपनी हरे रंग की साड़ी उतारकर लोगों को दे दी। साड़ी को सहारे के रूप में इस्तेमाल कर पानी में मौजूद लोगों को बाहर खींचा गया।

कुछ लोग साड़ी लेकर पानी के अंदर जाते और बाहर खड़े लोग उसे खींचकर वापस लाते। आखिरी बच्चे की तलाश में भी काफी समय लगा। उसे बाहर निकालने के बाद कंधे पर उठाकर बाहर लाया गया। लोगों ने मौके पर सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया। इसके बाद किसी को आटो, किसी को स्कूल बस और बाद में एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

साड़ी उतार कर दी, बेटे का टीशर्ट पहना

अनीता पहली बार पैराडाइज वैली गई थी। पहले जामण जाने की योजना थी, लेकिन बच्चो की जिद पर वैली पहुंचे थे। विशाल के अलावा 12 वर्षीय बेटी रौनक व भतिजा 10 वर्षीय दिव्यांश स्कूटी से पहुंचे थे। घटना के समय रौनक वीडियो बना रही थी। पानी का एक हिस्सा उथला दिखाई देता है, जबकि कुछ दूरी पर अचानक गहराई बढ़ जाती है। इसी कारण गहरे पानी का अंदाजा नहीं हो पाया और कुछ ही मिनट में स्थिति बदल गई।

विशाल ने तैरना गांव के कुएं, नदी और नालों में सीखा था। सभी को बाहर निकालने के बाद वह अपने बच्चों के साथ सबसे अंत में मौके से निकलीं। साड़ी देने के बाद अनीता ने बेटे का टीशर्ट पहन लिया था। उसी साड़ी में मृतक विजय को उपर ले जाया गया। बाद में बेटा साड़ी लेकर आया और वहीं फटी हुई साड़ी लपेट कर अनीता घर पहुंची।

हादसे होते रहे, बचाव के इंतजाम नहीं हुए

पैराडाइज वैली में हादसों का सिलसिला नया नहीं है। अगस्त 2025 में आठ दोस्तों के साथ नहाने गए 17 वर्षीय फैजान पुत्र अनवर खान की डूबने से मौत हुई थी। सितंबर 2022 में भी यहां हादसे में दो किशोरों की मौत हुई थी। इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम सवालों में हैं। 27 जुलाई को नईदुनिया की पड़ताल में सामने आया था कि कलेक्टर के निर्देश के बाद भी घटनास्थल पर न सुरक्षा बोर्ड लगे, न गार्ड और न रेस्क्यू टीम तैनात हुई।

शहर से करीब 11 किमी दूर पहाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच बहती जामण नदी बारिश में आकर्षण बनती है। इंटरनेट मीडिया रील्स से भीड़ बढ़ी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पीछे छूट गई। रविवार को हुए हादसे के बाद करीब एक घंटे तक सहायता नहीं पहुंच सकी थी। 27 जुलाई को नईदुनिया की पड़ताल में सामने आया था कि कलेक्टर के निर्देश के बाद भी घटनास्थल पर न सुरक्षा बोर्ड लगाए गए थे, न गार्ड और न ही रेस्क्यू टीम तैनात थी।

शराब से भरा कंटेनर पलटा, सड़क पर बिखरी बोतलें

माही की गूंज, बड़वानी।

ठीकरी थाना क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात शराब से भरा कंटेनर पलट गया। हादसा खुरमपुरा और ठीकरी के बीच शेर पंजाब ढाबे के सामने हुआ। कंटेनर पलटने से शराब की बोतलें राजमार्ग और आसपास के रास्ते पर बिखर गईं, जिससे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई। हादसे में चालक कंटेनर में फंस गया था, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला।

हादसे के बाद ढाबे पर मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और कंटेनर में फंसे चालक को बाहर निकाला। इसके बाद राजमार्ग एंबुलेंस की मदद से चालक को ठीकरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। चालक की हालत के संबंध में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है।

चालक से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार कंटेनर महाराष्ट्र के नासिक से हरियाणा के गुरुग्राम जा रहा था। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी बोतलों पर श्सुला वाइनयाड्र्स शिराज कैबरनेट 2025 प्रीमियम कलेक्शनश् लिखा हुआ था। बोतलों पर श्केवल हरियाणा में बिक्री के लिएश् का टैग भी लगा था।

हादसे के कई घंटे बाद तक आबकारी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, शराब की वैधता और उसके परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ठीकरी थाना प्रभारी विकास बेनल ने बताया कि राजमार्ग पर कंटेनर पलटने की सूचना मिली थी। कंटेनर में शराब भरी हुई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति

संभाली और आबकारी विभाग को सूचना दे दी गई है। आबकारी विभाग की टीम के आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस

माही की गूंज, खरगोन।

बुधवार को 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी अकीदत और उत्साह के साथ मनाई गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल हुए।

जुलूस सुबह 9 बजे मस्जिद गोसिया से प्रारंभ हुआ। मस्जिद गोसिया के अध्यक्ष आरिफ खान केजीएन तथा मस्जिद अनवारे मुस्तफा के अध्यक्ष अनीस खान केजीएन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया।

इस अवसर पर संरक्षक काजिम अली सैय्यद, उपाध्यक्ष हाजी कलीम चिस्ती, आवेस अली सैय्यद, अयाज कादरी, तौसीफ खान सहित अनेक समाजजन मौजूद रहे।

जुलूस के दौरान शहर तकबीर और रिसालत की सदाओं से गूंज उठा। समाजजनों ने अल्लाह से सभी लोगों, रिश्तेदारों तथा मानव समाज की खुशहाली और गुनाहों की माफी के लिए दुआ की।

कार्यक्रम में पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को स्मरण करते हुए प्रेम, भाईचारे और ईमानदारी के संदेश को अपनाने की प्रेरणा दी गई। लोगों ने एक-दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दीं।

जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली थाना पुलिस तैनात रही। पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिट्टू सहगल तथा थाना प्रभारी बीएल मंडलोई सहित पुलिस बल ने पूरे जुलूस मार्ग पर निगरानी रखते हुए व्यवस्थाएं संभालीं।

होटल मैनेजर की डूबने से मौत

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।

बुधवार सुबह नर्मदा स्नान के दौरान उज्जैन निवासी आकाश रैकवार की डूबने से मौत हो गई। हादसा सुबह करीब साढे 8 बजे गोमुख घाट पर हुआ। आकाश अपने साथी कुणाल गुर्जर के साथ उज्जैन से ओंकारेश्वर आया था। दोनों उज्जैन के एक होटल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

आकाश के साथी कुणाल गुर्जर ने बताया कि आकाश ने सुबह करीब 3 बजे ओंकारेश्वर जाने की बात कही थी। इसके बाद दोनों ओंकारेश्वर पहुंचे और गोमुख घाट पर नर्मदा स्नान करने गए।

स्नान के दौरान आकाश गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे। उनकी सहायता से आकाश को पानी से बाहर निकाला गया।

कुणाल के अनुसार, आकाश को नाविकों और एसडीईआरएफ जवान गणेश की मदद से ममलेश्वर मंदिर क्षेत्र तक लाया गया। इसके बाद वाहन की सहायता से उसे सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक डॉ. रवि वर्मा ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

कुणाल गुर्जर ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर पाइप लगे होने के कारण वाहन को अस्पताल पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जिससे काफी समय नष्ट हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसडीईआरएफ का एक जवान कमर तक पानी में मौजूद था, लेकिन उसने आकाश को बचाने का प्रयास नहीं किया।

हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना शेष है।

थाना मांधाता के सहायक उपनिरीक्षक सतीश सोहनी ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को बताए सफलता के सूत्र

माही की गूंज, बड़वानी।

दिशा लर्निंग सेंटर में आयोजित प्रेरक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने विद्यार्थियों से दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने का आह्वान किया।

पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर अधिक उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं और कमियों की पहचान करने के लिए नियमित आत्मचिंतन करने की सलाह दी।

मानसिक तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए उन्होंने नियमित योग और प्राणायाम अपनाने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं से गलत गतिविधियों और बुरी संगति से दूर रहकर अनुशासित जीवन जीने की अपील की। संवाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने भगवद्गीता, रामायण और महाभारत के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यपथ पर अडिग रहते हुए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने उनका आभार व्यक्त किया।

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप

माही की गूंज, खंडवा।

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर गांव के ही एक विवाहित युवक के खिलाफ दुष्कर्म तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार आरोपी ने रास्ते में किशोरी को रोककर जबरन अपने साथ खेत में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने किसी को जानकारी देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

छैगांवमाखन थाना प्रभारी एसएन पांडेय ने बताया कि घटना की शुरुआत 28 मार्च 2026 को हुई थी। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि आरोपी ने इसके बाद भी उसे धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह कक्षा 9 तक पढ़ी है और गांव में रहती है। गेहूं कटाई के दौरान 28 मार्च को वह अकेली अपने मामा के खेत में गेहूं लेने जा रही थी। गांव के बाहर नीम के पेड़ के पास उसे उसके मोहल्ले में रहने वाला युवक मिला, जो उसके मामा का पुत्र है।

शिकायत के अनुसार आरोपी ने किशोरी का हाथ पकड़कर उसे खेत की ओर ले गया और वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार जब उसने वहां से भागने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

डर के कारण किशोरी ने घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं दी। शिकायत में उसने बताया कि इसके बाद भी आरोपी उसे अकेला पाकर धमकाता रहा और दो-तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

लगातार धमकियों से परेशान होकर 24 अगस्त 2026 को किशोरी ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने उसे लेकर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। किशोरी के नाबालिग होने के कारण पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एन)/6 लगाई गई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 64(2)(एम), 64(एफ) तथा 351(3) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। धारा 351(3) आपराधिक धमकी से संबंधित है, जबकि अन्य धाराएं यौन अपराधों से जुड़े गंभीर प्रावधानों से संबंधित हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान की अनदेखी के चिंताजनक संकेत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का प्रस्ताव दिया है। यह विभाग करीब दो दशक से मौजूद है, लेकिन अब जाकर इसकी नींद खुली कि भारत में हेल्थ रिसर्च पर कोई खास नीति नहीं है।

जुलाई में जारी अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मुख्य संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए रखे फंड का महज 3.3 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को क्रमशः 32 और 15 फीसदी। भारत का आरएंडडी हेतु रखा गया फंड बहुत कम है -जीडीपी का 0.84 फीसदी, जबकि चीन का 2.58 प्रतिशत है।

नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के जाहिर लक्ष्यों में से एक बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना है। लक्ष्य है कि स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश को जीडीपी के अंशानुसार वर्तमान में 0.024 फीसदी से बढ़ाकर 2037 तक 0.072 प्रतिशत और 2047 तक 0.15 फीसदी करना है। भले ही यह बढ़ोतरी बड़ी लग सकती है, लेकिन भारत के मौजूदा और अनुमानित बीमारियों के बोझ और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों की तुलना में यह बहुत कम है। इसके अलावा, प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए समय-सीमा बहुत दूर की है, लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य नहीं व इसके लिए कोई बजटीय मदद भी नहीं है।

प्रस्तावित बढ़ोतरी कैसे हासिल की जाएगी, ज़्यादा समस्या वाली बात यह है। नीति में कहा गया है : 'सार्वजनिक निवेश धीरे-धीरे बढ़ेगा, और इसके साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निजी, परोपकारी और गैर-सरकारी निवेश भी होगा'। यह औपचारिक रूप से स्वास्थ्य अनुसंधान में निजी निवेश के लिए द्वार खोलना है।

सरकार जिस तरह निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, वह ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। नीति में कहा है कि निजी कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक संस्थानों में आरएंडडी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकेगा, और सेहत अनुसंधान विभाग ऐसी फंडिंग को आसान बनाने को ज़रूरी नीतियां बनाएगा।

यह तरीका दवा या वैक्सीन विकास के लिए मौजूदा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से अलग है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के विकास जैसी अहम परियोजना के तहत फार्मा कंपनियां और सार्वजनिक संस्थान शामिल होते थे। अगर किसी कंपनी-चाहे वह फार्मा कंपनी हो या कोई और -अथवा किसी कंपनी द्वारा प्रायोजित परोपकारी संस्था से सीएसआर फंड लेने की इजाज़त दी जाएगी, तो इससे अनुसंधान में पक्षपात हो सकता है या कोई छिपा एजेंडा हो सकता है। जैसे कि पर्यावरण से जुड़े सेहत जोखिम (वायु प्रदूषण, तंबाकू, शराब का प्रभाव), पेशेवराना स्वास्थ्य खतरे, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विवादित विषयों पर 'वैज्ञानिक संदेह' निर्मित करना।

अजीब बात है कि एक तरफ़ सरकार ने विदेशी

योगदान से जुड़े नियमों के नाम पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कुछ बड़े स्वास्थ्य एनजीओ और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के जमीनी अनुसंधान अध्ययनों की राह में रोड़े अटका दिए तो दूसरी तरफ़ वह उद्योग जगत और विदेशी संस्थानों द्वारा हेल्थ रिसर्च करने की राह खोल रही है। जबकि स्वदेशी अनुसंधान करने वालों को अभी भी भारतीय व विदेशी अनुसंधानकर्ताओं के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।

ऐसा लगता है कि पूरी सोच स्वास्थ्य अनुसंधान को हर स्तर पर केंद्रीकृत करने और नौकरशाही तंत्र स्थापित करने की है। नीति में एक 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा' बनाने की बात कही गई है जो वृहद स्तर पर प्राथमिकताएं तय करेगा और इस एजेंडा को लागू करने के लिए तीन-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र होगा। सबसे ऊपर 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' होगी जो रणनीतिक दिशा तय करेगी। इसके मुखिया 'प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार' होंगे और इसमें कई नौकरशाह (विज्ञान विभागों के सचिव) सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। दूसरे स्तर पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग होगा, जो मुख्य समन्वय एजेंसी के तौर पर काम करेगा, और तीसरे स्तर पर आईसीएमआर होगा, जिसका जिम्मा वैज्ञानिक एवं तकनीक संबंधी कार्य करना होगा।

प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था राज्यों की भूमिका को कमज़ोर करती है और इस बात को नज़रअंदाज़ करती है कि जनस्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और 'मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान' संविधान की समवर्ती सूची में है। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तय करने का अधिकार 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' को देने से राज्य सिर्फ़ क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएंगे। नीति में कहा गया है, 'राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्वास्थ्य ज़रूरतों के हिसाब से काम करने और कार्यक्रम बनाने, बतौर सेवा प्रदाता और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में मदद करेंगे'।

नीति एक और अहम बदलाव लाती है- 'एकीकृत स्वास्थ्य' को बढ़ावा देने के नाम पर आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक मेडिसिन के लिए रखे अनुसंधान फ़ंड का इस्तेमाल करने की इजाज़त देना। ऐसा तब हो रहा है जब इन पद्धतियों के लिए आयुष मंत्रालय के तहत अलग से रिसर्च फंड और उसके द्वारा चलाए जा रहे तंत्र मौजूद हैं। इससे 'पुष्टिकरण विज्ञान' को बढ़ावा मिलेगा, मसलन, गोमूत्र से इलाज जैसे पारंपरिक ढंग की 'आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हुई पुष्टि' दिखाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जैसी अन्य एजेंसियों से फ़ंडिड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ऐसा पहले ही हो रहा है।

भारत न सिर्फ़ भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता वाला देश है, बल्कि यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की ज़रूरतों और स्वास्थ्य तंत्र तक पहुंच में असमानताएं भी हैं। मसलन, केरल का स्वास्थ्य सूचकांक और चुनौतियां बिहार या ओडिशा से अलहदा हैं। राज्यों पर केंद्र से थोपा गया एजेंडा लागू करवाने के बजाय, उन्हें अपनी-अपनी प्राथमिकताओं व ज़रूरतों के आधार पर अपना-अपना स्वास्थ्य अनुसंधान ढांचा बनाने और विकसित करने में मदद व मार्गदर्शन दिया जाए। स्वास्थ्य अनुसंधान का मतलब सिर्फ़ नई तकनीक का परीक्षण या नई वैक्सीन और दवाएं बनाना नहीं। इसके परिणाम स्वास्थ्य नीति और बजट तय करने वाले हों। इसका बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य तंत्र के कामकाज व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ा है, ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें। स्वास्थ्य अनुसंधान एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-आर्थिक कारकों से गहरी जुड़ी है। मसलन, शहरी गरीब और आदिवासी जैसे हाशिए पर मौजूद समूहों व समुदायों की सेहत समस्याओं पर अक्सर कम रिसर्च होती है। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले गए। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर रिसर्च करने को प्रेरित करने की ज़रूरत है।

दिनेश सी शर्मा

दीर्घकालीन जरूरतों की खातिर एक समर्पित स्वास्थ्य अनुसंधान नीति बनाने का विचार लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। हालांकि, यह नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है-अनुसंधान एंजेडा विकसित करने को अपनाया केंद्रीकृत तरीका, निजी क्षेत्र को अहम भूमिका देना व आधुनिक मेडिकल स्वास्थ्य अनुसंधान में पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ने वाला एजेंडा फिट करना- वह बल्कि ज्यादा हानिकारक है।

छात्रावास में बालिकाओं के बाल काटने और भोजन में इल्ली की शिकायत

माही की गूंज, धार।

आदिवासी अंचल की बालिकाओं के लिए संचालित छात्रावास में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। धामनोद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले संत फ्रांसिस जेवियर बालिका छात्रावास, धानी में रह रही बालिकाओं ने परेशानियों से अभिभावकों को अवगत कराया।

बालिकाओं की शिकायतों के बाद अभिभावकों ने जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश रावल और तहसीलदार अंजलि गुप्ता को दी। सूचना पर दोनों अधिकारी छात्रावास पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोनिका सिंह भी मौजूद रही। बालिकाओं के बाल काटने की शिकायत मिली थी। कैमरे खंगाले गए हैं। हालांकि इस मामले में कोई प्रणाम नहीं मिले है।

नियमित रूप से नहाने नहीं दिया जाता

निरीक्षण के दौरान बालिकाओं ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें नियमित रूप से नहाने नहीं दिया जाता और सप्ताह में केवल दो बार ही नहाने की अनुमति दी जाती है। बालिकाओं ने इसे लेकर परेशानी जताते हुए कहा कि छात्रावास में रहने के दौरान उन्हें स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है।

आदिवासी क्षेत्र से आकर छात्रावास में रहने वाली इन बालिकाओं के लिए यह व्यवस्था चिंता का विषय बनी हुई है। बालिकाओं ने छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर शिकायत की। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि भोजन में इल्ली मिलने जैसी स्थिति सामने आई है। इसके अलावा भोजन और छात्रावास की अन्य व्यवस्थाओं में भी कई तरह की कमियां होने की बात बालिकाओं ने बताई।

अब जांच और कार्रवाई पर नजर

बालिकाओं की शिकायतों के बाद छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आई शिकायतों के आधार पर अब संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर अभिभावकों और स्थानीय लोगों की नजर है।

छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उन्हें शिक्षा के लिए घर से दूर रहकर ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीईआ राजेश रावल ने कहा कि खाने व पानी आदि की शिकायत पर नोटिस दे रहे है।

संत फ्रांसिस जेवियर बालिका छात्रावास, धानी की प्रभारी अर्चना सिस्टर ने बताया कि हम आज बहुत ही दुखी है। 56 साल से सेवा कार्य कर रहे है लेकिन बच्चों ने इस तरह के आरोप लगाए। सारे आरोप निराधार है। हम नियमों से ही बच्चों के होस्टल का संचालन करते है।

बिना हेलमेट ईंधन वितरण पर रोक

माही की गूंज, धार।

जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में कलेक्टर ने पिछले सड़क हादसों की गहराई से समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग हॉटस्पॉट और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के कड़े निर्देश दिए; उन्होंने चिन्हांकन से पहले और बाद की घटनाओं व मौतों का ब्योरा लेते हुए वहां तुरंत गति अवरोधक, संकेतक और लाइटिंग लगाने तथा दुर्घटना स्थलों का संयुक्त भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन बिल्कुल न दिया जाए और इसकी सतत मॉनिटरिंग हो। इसके साथ ही, %गोल्डन ऑवर% पर विशेष फोकस करने, स्कूल बसों, स्लीपर बसों, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और %ड्रिंक एंड ड्राइव% के खिलाफ शून्य सहनशीलता अपनाते हुए लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। ट्रकों के %ब्लाइंड स्पॉट% पर विशेष सावधानी बरतने, विभागों को मासिक कार्ययोजना तैयार करने तथा %राहवीर योजना% का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देने के साथ ही सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता लाने पर जोर दिया गया।

अवैध जलाऊ लकड़ी से भरा ट्रक जब्त

माही की गूंज, धार।

जिले में वन तस्करों के विरुद्ध वन विभाग द्वारा लगातार सख्त व प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में गत रात्रि वनमंडलाधिकारी विजयानंथम टी.आर. के कुशल निर्देशन तथा उप वनमंडल अधिकारी धार सुरेश बरोले के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी धार ने जानकारी देते हुए बताया कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल एक विशेष गश्ती एवं चेकिंग दल का गठन किया गया था। रात के समय लेबड ब्रिज मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक (क्रमांक एमपी-09, एचजी-0586) तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसे वन अमले द्वारा घेराबंदी कर रुकवाया गया।वाहन की सघन तलाशी लेने पर उसमें लगभग 5 टन जलाऊ लकड़ी के गुटके भरे पाए गए। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गणेश पिता नाथूलाल (निवासी धार) बताया। प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अवैध लकड़ी प्रतापसिंह चौहान (हेडसाब) की आरा मशीन %विनय टिम्बर मार्ट, बदनावर% से भरकर %श्री पेपर कंपनी, इंडोरोमा, पीथमपुर% ले जाई जा रही थी। मौके पर जब वाहन चालक से परिवहन संबंधी वैध अनुज्ञा पत्र (परमिट) व दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2022 के प्रावधानों के तहत मौके पर ही पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की। जब्त की गई लगभग 5 टन जलाऊ लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य 30,000 रुपए आंका गया है। जप्तशुदा वाहन एवं लकड़ी को सुरक्षित मांडव रोड स्थित रेस्ट हाउस, धार लाया गया है तथा मामले में अग्रिम वैधानिक जांच प्रचलित है।इस पूरी उल्लेखनीय एवं सफल कार्यवाही में वन परिक्षेत्र धार के मैदानी स्टाफ द्वारा उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन किया गया है। वन विभाग द्वारा दी गई इस चेतावनी से अवैध लकड़ी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी।

'लग्जरी कार, आईएएस जैसा भौकाल', हैरान कर देगी तृप्ति की कहानी

भोपाल।

फर्जी आईएएस बनकर लोगों पर रौब जमाने और ठगी करने के आरोपों में घिरी तृप्ति राजपूत के भोपाल कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। चंदेरी पुलिस तृप्ति और उसके भाई को भोपाल लेकर पहुंची, जहां बागमुगालिया स्थित उसके घर और अल्कापुरी स्थित ससुराल में जांच की गई। पुलिस को यहां से फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटरहेड और ठगी से जुड़े अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 'भारत सरकार' लिखी इनोवा कार भी जांच के दायरे में है, जिसका इस्तेमाल तृप्ति कथित तौर पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर प्रभाव जमाने के लिए करती थी। साथ ही चंदेरी में एमपी पर्यटन की एडिशनल हेड बनकर एक कारोबारी से 9.80 लाख रुपये की ठगी और फर्जी आईएएस बनकर उससे शादी भी की।

आईएएस अधिकारी बताकर लोगों पर जमाती थी प्रभाव

पुलिस की जांच में सामने आया है कि तृप्ति राजपूत खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों पर प्रभाव जमाती थी। इसके लिए वह सरकारी अधिकारी जैसा पूरा रुतबा दिखाती थी। बताया जा रहा है कि आरोपी किराए की ऐसी इनोवा कार का इस्तेमाल करते थे, जिस पर 'भारत सरकार' लिखा हुआ था। सरकारी गाड़ी जैसी दिखने वाली इस इनोवा के जरिए लोगों के बीच फर्जी अफसर होने का प्रभाव बनाया जाता था। जांच के दौरान फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटरहेड और अन्य दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके अलावा महंगे आईफोन और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े सामान की भी जांच की जा रही है।

पुलिस को आशंका है कि इन तमाम चीजों का इस्तेमाल लोगों को भरोसे में लेने और फर्जी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए किया जाता था। तृप्ति राजपूत पर चंदेरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म की एडिशनल हेड बनकर एक बिजनेसमैन से करीब 9 लाख 80 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है। इसी दौरान उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कारोबारी से शादी भी की।

पुलिस इन तथ्यों की भी कर रही है जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी पहचान के जरिए उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। भोपाल में पुलिस ने तृप्ति के घर और ससुराल में दस्तावेजों और अन्य सामान की बारीकी से जांच की। खासतौर पर फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटरहेड, सरकारी पहचान से जुड़े दस्तावेज और भारत सरकार लिखी इनोवा के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी सरकारी पहचान पत्र और लेटरहेड तैयार करवाने में कौन-कौन लोग शामिल थे।

किराए की सरकारी गाड़ी जैसी दिखने वाली इनोवा किससे ली गई और उसका इस्तेमाल किन-किन जगहों पर किया गया, इसकी भी जांच होगी। महंगे होटल, आईफोन, सरकारी गाड़ी और फर्जी पहचान के जरिए रुतबा दिखाकर ठगी करने वाले इस नेटवर्क की परतें अब पुलिस धीरे-धीरे खोल रही है। चंदेरी पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ भोपाल में मिले सबूतों को भी केस की जांच में शामिल करेगी।

बिना अनुबंध 10 हजार में बांटी बेशकीमती कैंटीन

जबलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन संचालन को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फर्जीवाड़ा और विवाद सामने आया है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लगभग 4,000 वर्गफीट की विशाल और बेशकीमती कैंटीन का कार्यादेश नियमों को दरकिनार कर बिना किसी विधिवत अनुबंध के जारी कर दिया गया।

यह गंभीर मामला संज्ञान में आते ही कुलगुरु (वीसी) प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब निविदा प्रक्रिया से लेकर कार्यादेश जारी करने तक की पूरी फाइल की गहन पड़ताल की जाएगी।

महिला समूह के हटते ही मेहरबान हुए अफसर

विश्वविद्यालय परिसर की करीब 4,000 वर्गफीट में फैली कैंटीन का संचालन पिछले वर्ष तक एक स्थानीय महिला समूह द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा था। किसी कारणवश जब समूह ने संचालन बंद किया, तो विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हो गई।

आरोप है कि अफसरों ने अंदरूनी मिलीभगत कर अपने एक चहेते व्यक्ति को आनन-फानन में महज 10,000 रुपए प्रतिमाह की नाममात्र दर पर कैंटीन संचालन का कार्यादेश थमा दिया, जिससे विश्वविद्यालय को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अफसरों की मेहरबानी- बिना अनुबंध 10 हजार रुपए में बांटी बेशकीमती कैंटीन, संदेह के घेरे में आए अधिकारी।

काउंसलिंग का आयोजन

माही की गूंज, धार।

जिला रोजगार कार्यालय, धार के तत्वावधान में शासकीय पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सादलपुर में एक दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मार्गदर्शन सत्र में विद्यालय के 95 बालक-बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा चयनित पैनल काउंसलर्स एवं विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। विषय विशेषज्ञों ने बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और उन्हें लक्ष्य निर्धारण करने की सही दिशा दिखाई।

जिला रोजगार अधिकारी सतीश डोडिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सही समय पर सही करियर का चुनाव ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।समारोह के अंत में जिला रोजगार कार्यालय के सहायक ग्रेड-दो भगवान गोयल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

महाकालेश्वर मंदिर में कांवड़ियों का हंगामा

माही की गूंज, उज्जैन।

महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब इंदौर से आए कावड़ यात्रियों और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ कावड़ यात्री नंदीहाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।

रोकने पर बढ़ा विवाद, धक्का-मुक्की के बाद मारपीट

आरोप है कि नंदीहाल में प्रवेश से रोकने पर विवाद बढ़ गया। कावड़ यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं के बीच भी कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई।

सुरक्षाकर्मी के सिर में लगी चोट

विवाद के दौरान मंदिर की निजी सुरक्षा एजेंसी में तैनात एक गार्ड घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगने के बाद तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि भीड़भाड़ वाले समय में इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए।

विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल से जुड़े होने का दावा

मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, इंदौर से आए कावड़ यात्रियों में कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और पहचान की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

मंदिर प्रबंधन ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

घटना की जानकारी सामने आने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है। प्रबंधन की ओर से संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर थाना महाकाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस अब घटना से जुड़े लोगों की पहचान और पूरे विवाद की परिस्थितियों की जांच करेगी।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी सबसे बड़ी प्राथमिकता

महाकाल मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नंदीहाल जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विवाद की घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे।

झाबुआ के किसानों की मांगें मानीं, सत्ता ने बचाई स्थानीय नेताओं की सियासी जमीन

मंत्री निर्मला भूरिया और सांसद अनीता नागरसिंह चौहान के सामने किसानों का भरोसा बचाने की थी चुनौती

माही की गूंज, झाबुआ।
धर्मेंद्र पंचाल

झाबुआ में किसानों के आंदोलन ने सत्ता और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता था। किसानों की मांगें यदि नहीं मानी जातीं और धरना लंबा खिंचता, तो केवल कलेक्ट्रेट का घेराव ही नहीं बढ़ता, बल्कि झाबुआ जिले के स्थानीय नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसकने का खतरा भी पैदा हो सकता था। सत्ता ने समय रहते इस खतरे को भांपा। किसानों से संवाद हुआ, मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और चार गुना मुआवजे की मांग मानने की दिशा में फैसला हुआ। इस तरह एक तरफ किसानों को अपने आंदोलन की सफलता मिली, तो दूसरी तरफ सत्ता ने भी समय रहते अपनी सियासी जमीन बचाने की पूरी कोशिश की। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है।

बदनावर-टिमरवानी फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण का सवाल किसानों के लिए उनकी जमीन, आजीविका और भविष्य का सवाल था। लेकिन जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ा, यह स्थानीय राजनीति के लिए भी प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रश्न बनता गया। झाबुआ जैसे जिले में किसान और ग्रामीण मतदाता केवल चुनाव के समय याद किए जाने वाला वर्ग नहीं है। जमीन, मुआवजा, फसल, सिंचाई और रोजगार जैसे मुद्दे सीधे राजनीतिक भरोसे को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि किसानों की नाराजगी को समय रहते समाधान नहीं मिलता, तो उसका असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ना संभव था।

आंदोलन के बीच सांसद अनीता नागरसिंह चौहान का किसानों के धरने में पहुंचना महज औपचारिक राजनीतिक उपस्थिति नहीं माना जा सकता। किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पहल इस बात का संकेत था कि, मामला स्थानीय प्रशासन की सीमा से बाहर निकल चुका है। मंत्री निर्मला भूरिया के लिए भी यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। किसानों की नाराजगी उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहती तो उसका असर केवल एक आंदोलन तक सीमित नहीं रहता। जनप्रतिनिधि के लिए जनता की शिकायत को समय रहते समाधान तक पहुंचाना प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ-साथ राजनीतिक आवश्यकता भी बन जाता है। यानी सत्ता पक्ष के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं थी कि, किसानों को कैसे समझाया जाए, बल्कि यह भी थी कि किसान यह महसूस करे कि, उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है।

दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया का किसानों के बीच पहुंचना विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता का संकेत था। किसी भी किसान आंदोलन में विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है। यदि आंदोलन लंबा चलता, मांगें नहीं मानी जातीं और किसानों की नाराजगी बढ़ती, तो यही मुद्दा विपक्ष के हाथ में सरकार के खिलाफ एक प्रभावी राजनीतिक हथियार बन सकता था। इसलिए मुख्यमंत्री स्तर पर किसानों से संवाद और चार गुना मुआवजे की मांग को स्वीकार करने का निर्णय केवल प्रशासनिक समाधान नहीं था। इसे राजनीतिक तनाव को समय रहते कम करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

किसानों के लिए चार गुना मुआवजे की मांग को स्वीकार किया जाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांग पर टिके रहे और अंततः सरकार को संवाद तथा समाधान की दिशा में आगे आना पड़ा। लेकिन सत्ता के लिए इसका दूसरा पहलू भी है। मुआवजा देकर सरकार ने केवल किसान का विवाद नहीं सुलझाया, उसने संभावित राजनीतिक असंतोष को भी समय रहते शांत किया। यही वजह है कि, इस निर्णय को केवल सरकार की जीत या किसान आंदोलन की जीत के रूप में देखना अधूरा होगा। यह दोनों पक्षों के लिए एक ऐसा समाधान है जिसमें किसान को उसकी मांग की दिशा में राहत मिली और सत्ता को संभावित राजनीतिक नुकसान से बचने का अवसर।

हालांकि घोषणा और निर्णय के बाद कहानी खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या चार गुना मुआवजा वास्तव में पात्र किसानों को समय पर मिलेगा...? क्या जमीन के साथ कुएं, मकान, पेड़ और दूसरी परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन होगा...? क्या अधिग्रहण के बाद किसानों की बची हुई जमीन तक पहुंच, रास्ते और अन्य व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा...? यदि इन सवालों का जवाब सकारात्मक रहा तो सत्ता यह दावा कर सकेगी कि, उसने आंदोलन को टकराव में बदलने के बजाय संवाद से समाधान किया। लेकिन यदि निर्णय के क्रियान्वयन में देरी हुई या किसानों को फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े, तो आज शांत हुआ असंतोष दोबारा राजनीतिक सवाल बन सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम में सांसद अनीता नागरसिंह चौहान और मंत्री निर्मला भूरिया की भूमिका भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी। किसानों के बीच पहुंचना और उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना पहला चरण था। अब उस आवाज को प्रशासनिक निर्णय और वास्तविक राहत में बदलवाना अगली जिम्मेदारी है। दूसरी ओर विपक्ष की भूमिका भी केवल धरना स्थल पर मौजूदगी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि किसानों की मांग स्वीकार हो चुकी है तो अब विपक्ष को भी यह देखना होगा कि, सरकार अपने निर्णय को कितनी गंभीरता से लागू करती है।

राजनीति में किसी मुद्दे से तत्काल चुनावी परिणाम निकालना आसान नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाला असंतोष धीरे-धीरे राजनीतिक धारणा में बदलता है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि, किसान आंदोलन से किसी नेता की राजनीतिक जमीन खिसक गई थी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि, किसानों की नाराजगी को लंबे समय तक अनदेखा करना स्थानीय नेतृत्व के लिए राजनीतिक जोखिम बन सकता था। समय रहते समाधान ने इस जोखिम को फिलहाल टाल दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि, विकास और किसान के हितों को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय सरकार को ऐसा रास्ता बनाना होगा जिसमें विकास परियोजना भी आगे बढ़े और प्रभावित परिवारों को न्याय भी मिले। सड़क, विकास की जरूरत है लेकिन उस सड़क के लिए जमीन देने वाले किसान को यह भरोसा भी चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है।

फिलहाल चार गुना मुआवजे के फैसले ने आंदोलन की आग को ठंडा किया है और सत्ता ने संभावित राजनीतिक नुकसान से अपनी जमीन बचाने की कोशिश की है। लेकिन स्थायी राजनीतिक भरोसा, घोषणाओं से नहीं बनता, वह तब बनता है जब घोषणा का लाभ किसान तक पहुंचता है।

आखिरकार किसान यह याद नहीं रखेगा कि, उसके धरने में कौन कितनी देर बैठा था। वह याद रखेगा कि, उसकी जमीन का सही मुआवजा मिला या नहीं। और आने वाले समय में झाबुआ की सियासत में यही तय कर सकता है कि, किसकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती है और किसकी धीरे-धीरे खिसकती है।

विवादित रन्नी सरपंच पति पर एक और आरोप

सरपंच पति ने शासकीय तालाब बनाने के नाम पर निजी पट्टे वाली भूमि पर किया अवैध खनन

माही की गूंज, खवासा।

-उक्त पट्टे वाली निजी भूमि पर सरपंच पति ने अपनी दबंगई के साथ सरकारी कार्य बताकर अवैध खनन कर जमिन पर कब्जा करने का किया प्रयास।

जब जनता का विश्वास मत के माध्यम से व्यक्ति को मिलता है तो वह जनप्रतिनिधि किसी जाति, समाज, पक्ष-विपक्ष का नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि का कार्य है सभी के हक में व नियमानुसार कार्य करें न कि अपने आतंक का पर्याय बन लोगों को डराए-धमकाएं।

मामला खवासा चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत रन्नी का है जहां महिला सरपंच है लेकिन पंचायत का पूरा क्रियान्वयन उसका पति अशोक झोड़ियां ही करता है।

पिछले समय में पत्नी के सरपंच बनने के बाद कई विवादित मामले सरपंच पति अशोक झोडिया के विरुद्ध सामने आए। मामले भी दर्ज हुए, यहां तक कि जिला कलेक्टेउट्र कार्यालय में जिला बदर कार्यवाही वाली सूची में अशोक झोड़ियां अपना नाम भी दर्ज करवा चुका है।

इसी विवादित पृष्ठभूमि के चलते एक और अशोक झोड़िया के विरुद्ध अपनी मनमानी व आतंक का पर्याय बन चुका अशोक झोड़ियां की दादागिरी का मामला सामने आया है और उसकी शिकायत भी नामजद पुलिस चौकी खवासा में दर्ज करवाई है। जिसकी जांच पुलिस कर रही है और एक और संगीन मामला अशोक झोड़िया के विरुद्ध दर्ज होने की संभावनाएं बन गई है।

यह अनियमितता व विवाद

मामला कुछ यह सामने आया कि, रन्नी निवासी शैतान, रादु एवं सरदार पिता भीमा की पट्टेदार भूमि सर्वे नंबर 163 रकबा 0.40 हेक्टेयर पर शासकीय कार्य तालाब बनाने के नाम पर बिना किसी अनुमति के गुमराह कर अपनी मनमानी के साथ सरपंच अशोक झोड़िया ने अवैध मोरम का निजी भूमि पर खनन किया। जब लोगों को पता लगा कि, किसी प्रकार का कोई तालाब बनाने संबंधी शासकीय स्वीकृति नहीं थी और सरपंच पति अशोक झोड़िया ने अपनी बदनियति के साथ पट्टेधारी अन्य निजी भूमि को अपने कब्जे में करने की नियत के साथ अवैध रूप से मोरम खनन किया गया।

उक्त जानकारी के बाद पट्टेधारी तीनों भाई शैतान, रादु,सरदार के साथ अन्य ने ग्राम के युवा मुकेश डाबी के साथ मौके पर अपनी निजी भूमि का वीडियो बनाकर अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर की। जिसमें बताया गया कि, सरपंच पति अशोक झोड़िया ने नियम कायदों को ताक में रख अन्य की निजी भूमि पर अवैध मोरम का खनन किया गया। और बताया गया कि, उक्त मोरम का उपयोग शासकीय कार्य में बन रहे तालाब में किया जाएगा लेकिन कोई शासकीय तालाब नहीं बनाया गया। और अवैध कब्जे की नीयत से सरपंच पति अशोक झोड़िया ने नियम कायदे को ताक में रख उक्त घृणित कार्य किया।

जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो ग्राम के सजक युवा मुकेश डाबी को फोन कर अशोक झोड़िया ने गाली-गलौज के साथ धमकाने का प्रयास किया और सरपंच पति ने मुकेश को कहा कि, तूने किस अधिकार से वीडियो-फोटो बनाएं और मुकेश को निपटाने तक की बात सरपंच पति ने कही।

सरपंच पति द्वारा घृणित कृत्य करने के बाद अपनी गलती मानने की बजाय धमकाएं जाने पर पट्टेधारी एवं मुकेश ने सामूहिक रूप से मय ऑडियो-वीडियो के पुलिस चौकी खवासा में धरना दिया व रिपोर्ट दर्ज करवाई है व बिंदुवार मामले की जांच कर अशोक झोडिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामले में समाचार लिखे जाने के पूर्व खवासा पुलिस से जानकारी ली तो पुलिस ने बताया कि, मामले में शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई है पुलिस मामले की बिंदुवार जांच कर रही है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरी जानकारी देने की बात पुलिस ने कही है।

किसानों के भागीरथी प्रयास दरकिनार, अपने ही पार्टी के नेताओं के नाम हजम नहीं हो रहे भाजपाई नेताओं को

माही की गूंज, पेटलावद।

भाजपा नेताओं द्वारा की सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें भाजपा की सांसद, मंत्री नागरसिंह चौहान का नाम तक नहीं लिखा।

बदनावर-टीमरवानी मार्ग में भूमि अधिग्रहण में दिए जाने वाली मुआवजा राशि को लेकर किसानों ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे। कई बार किसानो ने आवेदन, निवेदन के बाद जब किसानो की नहीं सुनी गई तो किसान कलेक्टेउट्र में धरने पर बैठ गए। पांच दिनों तक चले धरनें में जम कर राजनीति हुई, पक्ष-विपक्ष के नेता धरना स्थल पर पहुंच गए। आखिर मुख्यमंत्री को किसानों की मांग मान कर चार गुना मुआवजा राशि देने की घोषणा वीडियो काल के जरिए सभी किसानों के बीच की गई। इस दौरान क्षेत्र की सांसद अनीता नागरसिंह चौहान, मंत्री नागरसिंह चौहान ओर मंत्री निर्मला भूरिया भी भोपाल मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थी। जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ सोशल मीडिया पर श्रेय लेने की होड़ मच गई।

आंदोलन के दौरान दिखाई नहीं दी मंत्री भूरिया, भाजपा में दिखी फूट

किसान आंदोलन खत्म करने में मंत्री निर्मला भूरिया की भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई। भाजपा नेता उन्हीं की पार्टी के 3 बड़े नेताओं सांसद अनीता नागरसिंह चौहान, मंत्री नागरसिंह चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भुरिया इस धरने को खत्म करने के लिए खुद किसानो के धरना स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई गई। मंत्री निर्मला भूरिया झाबुआ में होकर भी धरना स्थल पर नहीं गई। मामला समाप्त होने के बाद श्रेय की होड शुरू हुई ओर सोशल मीडिया पर पोस्टर ओर पोस्ट का दौर शुरू हो गया। खास कर सारंगी मंडल से जिसमे मंत्री निर्मला भूरिया के फोटो ओर नाम लिख कर उनको आंदोलन खत्म करने का श्रेय देने में जुट गए। जबकि वो किसानों से मिलने के लिए मंत्री महोदय धरना स्थल पर गई तक नहीं ओर किसान नेताओं को रेस्ट हाउस में बुलाकर बात की ओर मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन देकर धरना खत्म करने की बात की थी। जबकि मंत्री नागरसिंह चौहान ओर सांसद अनीता नागरसिंह चौहान एक दिन पहले से भोपाल मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क में होकर लगातार इस मामले में चर्चारत थे। खेर ये भाजपा का अंदरूनी मामला है किसने और कैसे मामले को निपटाया। लेकिन जब बात श्रेय लेने या देने की आई तो, सड़को पर उतरे किसान, किसान संगठन, बाप पार्टी, जयस संगठन को भूल कर भाजपा को श्रेय दिया। लेकिन टीम वर्क या सभी आंदोलन खत्म करने में लगे दूसरे भाजपा नेताओ को भी श्रेय देने की बजाए उनको दर किनार कर दिया ओर खुद को पार्टी भक्त कहने वाले निर्मला भक्ति करते दिखे। जबकि ये एक सामूहिक प्रयास थे किसान संगठनों का सामूहिक दबाओ के चलते नेताओं को जमीन पर आना पड़ा ओर भोपाल के नेताओं को झुकना पड़ा। भाजपा नेताओं के बीच बड़े स्तर पर एक बार फिर फूट देखने को मिली, भाजपा नेताओं ने अपनी पोस्ट ओर बैनरों में मुख्य भूमिका निभाने वाले मंत्री नागरसिंह चौहान ओर सांसद अनीता नागरसिंह चौहान के फोटो तो ठीक नाम तक लिखना उचित नहीं समझा। उधर कांग्रेस के लोग भी पीछे नहीं थे, धरने में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के कार्यकर्ता भी कांतिलाल भूरिया का लेटरपेड वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर किसानो की मांग को पुरा करने की मांग की गई थी।

किसान संगठनों के भागीरथी प्रयास रहे सफल

किसी भाजपा नेता ने किसानों की मांग को लेकर कोई मोर्चा नहीं खोला, आंदोलन के समर्थन में नहीं आए, कई बार मैदान में उतरे किसानों के साथ नहीं चले ना ही जिस नेता को श्रेय दिया जा रहा है उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों के साथ उनके घर, उनके गांव जाकर बैठक की। कई भाजपा नेताओं की भी भूमि इस सड़क निर्माण में जा रही है वो तो बैठे रहे कि ये लोग कर रहे है मेहनत इनका भला होगा तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन पार्टी के खिलाफ किसानो के साथ नहीं दिखेंगे लेकिन श्रेय की राजनीति शुरू हुई तो सबसे पहले सामने आए। जबकि पूरा आंदोलन किसान संगठनों के बैनर तले विगत 6 माह से जारी था। किसान संगठनों के दम पर क्षेत्र के प्रभावित किसानो को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

पुरानी गाइड लाइन के अनुसार मिलेगा मुआवजा...!

मुख्यमंत्री ने ही भले ही चार गुना मुआवजा देने की घोषणा कर दी है लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। जिस किसान संगठन के बैनर तले आंदोलन किया गया वो भी भाजपा से जुड़ा संगठन बताया जा रहा है, यहां तक कि पूरे आंदोलन को तय स्क्रिप्ट बताया जा रहा है। किसानों को जो मुआवजा मिलना है वो अप्रैल 2025 से पहले की गाइड लाईन से तय किया जाएगा। जबकि अप्रैल 2025 के बाद जमीनों की गाइड लाइन में चार गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है ओर किसानो को मुआवजा नई गाइड लाईन से मिलना था। किसानो के दूसरे संगठनों सहित क्षेत्र में सक्रिय बाप पार्टी की भी नई गाइड लाईन से मुआवजा राशि देंने की मांग है। बाप पार्टी इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में भी जा चुकी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422